

अगस्त, 2023

₹15

[www.mediamanch.in](http://www.mediamanch.in)

# मीडिया मंच

सम्पूर्ण समाचार पत्रिका



## अविश्वास का अंत

## उत्तराखंड: कुदरत का कहर



75  
आजादी का  
अमृत महोत्सव



# हमारा लक्ष्य

## बेहतर सुविधा बेहतर कनेक्टिविटी

5 शहरों में मेट्रो रेल संचालित  
5 शहरों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित



## डबल इंजन की सरकार विकास की दोगुनी रफ़्तार



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश



## मीडिया मंच

वर्ष - 26

अंक - 04



संपादक

तेज बहादुर सिंह  
सलाहकार संपादक  
हनुमान सिंह 'सुधाकर'

कार्यकारी संपादक  
वीरेन्द्र शुक्ल

समाचार संपादक  
वीरेन्द्र सिंह

वरिष्ठ फोटोग्राफर  
योगी, अजय सिंह इंद्रेश स्तोनी

मार्केटिंग  
सिग्मा ट्रेड विंग्स

लेआउट  
विष्णु बिसेन

स्वात्वाधिकारी

'मीडिया मंच पब्लिकेशन्स'  
के लिए प्रकाशक, मुद्रक,  
सम्पादक टी.बी. सिंह  
द्वारा प्रिंट आर्ट,  
कैन्ट रोड, लखनऊ  
से मुद्रित तथा जी-7,  
खुशनुमा कॉम्प्लेक्स,  
7-मीराबाई मार्ग,  
लखनऊ से प्रकाशित

RNI No. : UPHIN/1998/5628

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र  
लखनऊ होगा

वेबसाइट :

[www.mediamanch.in](http://www.mediamanch.in)

ई-मेल :

[mediamanch@gmail.com](mailto:mediamanch@gmail.com)  
[tejsingh007@yahoo.com](mailto:tejsingh007@yahoo.com)

मोबाइल-09415000151

## आवरण कथा

## अविश्वास का ...

08



22

## स्थायी स्तम्भ

वास्तु/ज्योतिष	04
अतिथि	05
ब्यूरोक्रेसी	30
खेल	40
चकल्लस	43
आंखिन देखी	45
स्वास्थ्य	46
सिनेमा	47
यूपीनामा	48

## कुदरत का .....

11

## स्टेशनों का कायाकल्प



वी.बी. सिंह

संपादकीय

जिस तरह 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और विस्तार का कार्य प्रारंभ हुआ है वह न केवल एक मेगा इवेंट ही है बल्कि इसे भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नए अध्याय के शुरुआत की तौर पर भी देखा जाना चाहिए। अभी तक इतनी बड़ी परियोजना सामने ही नहीं आई। 24,470 करोड़ की लागत के साथ 27 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को एक साथ लाभान्वित करने वाली यह योजना निश्चय ही प्रशंसनीय कहलाएगी। केवल यही नहीं जिस



द्वारा से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुनर्विकास की आधारशिला रखी और जिसके भव्य कार्यक्रम में राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र के नामी-गिरामी हस्तियों के साथ लाखों लोगों की भागीदारी हुई वह निश्चय ही स्मरणीय कार्यक्रम बन गया है। मोदी राज में सड़कों का विस्तार और उसकी रफ्तार को पहले ही नया आयाम मिल चुका था। अब केवल रेलवे स्टेशनों का ही मेकओवर बाकी रह गया था। वैसे गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण की शुरुआत अटल विहारी वाजपेयी सरकार में 'चुतर्भज योजना' के तहत हो चुकी थी। देश की लाइफ-लाइन कही जाने वाली रेलवे की दशा और दिशा में बहुत सुधार किया जाना बाकी था। काफी समय से रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और पुनरोद्धार की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। रेलवे में तो हर स्तर पर सुधार की गुंजाइश थी। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य के साथ रेलवे को निश्चय ही भविष्य में रेलवे की नई तस्वीर नजर आएगी। 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम प्रारंभ हो जाने से बहुत कुछ रेलवे में बदल जाएगा। इस दौरान 1309 स्टेशनों को समृद्ध भारत स्टेशन बनाए जाएंगे। 508 स्टेशनों के साथ मोदी की एक और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि उनकी सरकार के नौ वर्षों में देश में बिछाए गए रेलवे ट्रैक की लंबाई दक्षिण अफ्रीका, पोलैण्ड, यूक्रेन, यूके और स्वीडन के संयुक्त रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। यही नहीं, भारत ने दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और आस्ट्रेलिया के संयुक्त रेलवे नेटवर्क की तुलना में अधिक रेलवे ट्रैक बिछाए। सरकार रेल यात्रा को सुलभ करने के साथ-साथ सुखद बनाने के लिए भी कार्यरत है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सर्वाधिक 55-55 रेलवे स्टेशनों का जहां पुनर्विकास होना है तो वहीं बिहार में 49, महाराष्ट्र में 44, पश्चिम बंगाल में 37, मध्य प्रदेश में 34, असम में 32, ओडिशा में 25, पंजाब में 22, गुजरात में 21, तेलंगाना में 21, झारखंड में 20, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में 18-18, हरियाणा में 15 और कर्नाटक में 13 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे। यह अपने आप में एक रिकार्ड है जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में रेलवे के स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना है।

योजना में देशभर के 1309 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। पहले फेज में 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इस योजना के जरिए रेलवे स्टेशनों पर जनहित की तमाम सुविधाओं को देखा जा सकेगा और जनता को उसका सीधा लाभ भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री के अनुसार स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा। स्टेशन चमकेंगे तो माहौल बदलेगा। इतने सारे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से देश में विकास के लिए एक नया वातावरण बनेगा। अपग्रेड किए गए स्टेशनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' योजना कारीगरों की मदद करेगी और जिलों की ब्रांडिंग में सहायता करेगी। इस क्रम में यूपी के 55 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से रेल यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह सुविधा मिलने लगेगी। इस योजना से रेलवे स्टेशनों को अत्याधुनिक, उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं और विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे से लैस करने में मदद मिलेगी। □



# स्वतंत्रता दिवस पर एक ही दिन में 5 करोड़ पौधे रोपित अमृत स्तंभ का लोकार्पण



**मु**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'मेरी माटी-मेरा देश' अभियान के अंतर्गत अमृत वाटिका प्रांगण में अमृत स्तंभ का लोकार्पण किया।

इसके साथ ही अमृत वाटिका में हरिशंकरी के पौधे रोपित कर वृक्षारोपण महाभियान-2023 के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक ही दिन में पांच करोड़ पौधे रोपित किए जाने के अभियान का शुभारंभ भी किया।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने पिछले 9 अगस्त 2023 को 'माटी को नमन-वीरों का वंदन' कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृत स्तंभ की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्ष, प्रकृति और परमात्मा के साथ हम सभी को जोड़ने के माध्यम हैं। अमृत वाटिका और अमृत स्तंभ हम सब को आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्पों को याद दिलाएंगे और आगामी कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त से 30 अगस्त तक अमृतकाल के पहले साल में सभी भारतवासियों से कुछ संकल्प लेने का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी संकल्प के क्रम में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित

किए जा रहे हैं। पिछले 9 अगस्त 2023 को काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के साथ ही माटी को नमन, वीरों का वंदन कार्यक्रम शुरू किया गया है।

गौरतलब है कि 25 साल बाद आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा। इसी को सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके साथ ही पंचप्रण के नाम से पांच तरह के संकल्प दिलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत वाटिका अपने दायित्वों का निर्वहन इमानदारी पूर्वक करने की श्रृंखला का हिस्सा बनेगी। अमृत वाटिका में हरिशंकरी (पीपल, बरगद, पाकड़) के रूप में तीन पवित्र पेड़ों को जोड़ा गया है। 27 अलग-अलग नक्षत्रों के नाम पर पौधे रोपित कर नक्षत्र वाटिका और 9 ग्रहों के नाम पर पौधे रोपित कर नवग्रह वाटिका विकसित करने की सनातन परंपरा रही है।

योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि हमें अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। गुलामी के अंशों से हमें मुक्ति मिले। साथ ही साथ एकता और एकीकरण का भाव हमारे अंदर पैदा हो। इस रूप में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं बल्कि भारत माता हम सबके लिए सर्वोपरि हैं। मातृभूमि के लिए हम सभी का समर्पण होना चाहिए। मत और उपासना



हमारे लिए सेकेन्डी होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण है नागरिक कर्तव्य। अक्सर हम अपने अधिकारों की चर्चा तो करते हैं। लेकिन कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने संविधान को स्वीकार करने वाली तिथि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विधानमंडल में नागरिक कर्तव्यों पर चर्चा हुई।





आचार्य वंदना तिवारी  
7048200123



**वा**स्तु शास्त्र के सिद्धांत और वास्तु सम्मत व्यवहार जब हमारे निवास स्थल या कार्यालय की जगह पर लागू होते हैं तो हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं।

दूसरे शब्दों में ऐसी जगह जहाँ आपको अधिकतम समय बिताना और वो वास्तु के अनुरूप नहीं है तो आपके जीवन में परेशानी का कारण बन सकती है।

वास्तु के इस अंक में साज सज्जा द्वारा वास्तु सम्मत सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। वस्तुतः ये वस्तुएँ आपको सकारात्मक एवं ऊर्जावान बनाती हैं जिसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व के हर क्षेत्र पर पड़ता है।

**1. सकारात्मक तस्वीर-** वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर में निम्नलिखित तस्वीरें रखने की सिफारिश की जाती हैं:

धार्मिक चित्रों और देवी-देवता की तस्वीरें।  
प्राकृतिक सौंदर्य की तस्वीर जिसमें रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत वादियों की तस्वीरें।  
परिवार और प्रियजनों के साथ संबंधित तस्वीरें।  
अभिभावकों और गुरुजनों के चित्र।  
एकता और समृद्धि को प्रतिनिधित्व करने वाली तस्वीरें।

**2. विंड चाइम/घंटी-** प्रवेश द्वार पर विंड चाइम या अन्य मधुर ध्वनि यंत्र लगाकर नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं।  
घंटी के बजने से भी घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में मदद मिलती है।

**3. शंख-** शंख को घर में रखने से शुभता और समृद्धि की वृद्धि होती है। दक्षिणमुखी शंख को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है।

**4. सुगंधित वस्तु -** अगरबत्ती जैसी कोई भी सुगंधित वस्तु जलाने से घर की वातावरण शुद्ध होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप अगरबत्ती के जगह पर लोबान धूप का

# वास्तु अनुसार शुभ वस्तुएं

भी प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में सुगंधित वस्तु के बहुत से विकल्प भी आ गए हैं।

**5. पौधे -** पौधे घर में शुभ और हर्ष का अनुभव कराते हैं। मनी प्लांट स्नेक प्लांट आरेका पाम, पथोस, अलोवेरा इत्यादि घर के वातावरण को भी शुद्ध रखते हैं आक्सीजन की सप्लाई करने में मदद करते हैं।

**6. शुभ चिन्ह -** स्वास्तिक, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, आदि शुभ चिन्ह या यंत्र घर में शुभता का लाने के साथ-साथ भारतीय जीवन शैली का प्रतीक रहा है।

**7. दर्पण -** वास्तु शास्त्र में दर्पण का अत्यधिक महत्व है मगर इसके साथ-साथ इस ग्रंथ में इससे संबंधित दिशा स्थान का भी महत्व बताया गया है। यदि वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण को घर के उत्तर, पूर्व और ईशान भाग में रखना श्रेयस्कर होता है।

**8. प्रतिमा -** घर में आनंद और प्रसन्नता को बढ़ाने वाली प्रतिमाओं को रखना वास्तु संगत होता है। जहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा घर में रखने से समृद्धि और शुभकार्य में सफलता मिलती है वहीं भगवान विष्णु और उनकी शक्ति लक्ष्मी की प्रतिमा धन, समृद्धि, और सुख-शांति के लिए शुभ मानी जाती है।

घर में सूर्य भगवान की प्रतिमा रखने से ऊर्जा और जीवंतता की वृद्धि होती है।

पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा घर में रखने से भय से रक्षा होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है।

राधे कृष्ण की प्रतिमा भक्ति और आनंद का प्रतीक होती है और घर में प्रेम की भावना को बढ़ाती है।

ये प्रतिमाएं सम्मान के साथ स्थानीय संस्कार और धर्म के अनुसार रखी जानी चाहिए। प्रतिमाओं को धार्मिक स्थल में और शुभ दिनों पर विशेष अवसरों पर पूजन के लिए उपयुक्त जानना चाहिए।

इसी प्रकार बाल गणेश, देवी देवता की प्रतिमा, बुद्ध प्रतिमा बाल गोपाल आदि प्रतिमाएं आपके घर में प्रसन्नता और आनंद का अनुभव कराती हैं। जब भी आप प्रतिमाओं को रखते हैं, तो इन्हें सम्मानपूर्वक रखें और स्थानांतरित करें और नियमित रूप से पूजा और ध्यान करें।



इसके अलावा घर में सूप, दीपक, झूला प्रतिहारी, पंछियों के जोड़े, गाय बछड़े की प्रतिमा भी शुभ होती है।

ये शुभ वस्तुएं आपके घर में आत्मिक, भौतिक सकारात्मकता और शुभता का आनंद लेने में मदद कर सकती हैं। कभी-कभी घर में जगह की सीमा हो सकती है, इसलिए अपने पसंदीदा वस्तुओं को चयन करने में समझदारी से निर्णय लें। वस्तुतः अच्छी चीजों को देखने से आपके शरीर में अच्छा सिक्रीशन हो सकता है। प्रकृति के रंगों, सुंदर दृश्यों, और प्रिय विषयों को देखकर आपके मन को आनंदित होता है और सकारात्मक भावनाएं पैदा कर सकता है। इससे आपका मूड बेहतर हो सकता है और शारीरिक और आत्मिक तरीके से फायदा हो सकता है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः।



विनोद कुमार  
PCS

## नई सोच से बदली मैनपुरी की तस्वीर कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं : विनोद कुमार

वीरेन्द्र सिंह  
9410704385



**3** अभिनव प्रयोग के तौर पर गोशालाओं को फायदे के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले इनका रख-रखाव, संचालन हमारी लायबिलिटी थी। अब हमने गोशालाओं को एसेट के रूप में विकसित कर दिया है। गोशालाएं अब जिम्मेदारी नहीं संपत्ति हैं। गोबर बेचने का कार्य शुरू किया गया है। वर्मी कम्पोस्ट तैयार की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों को गोबर बेचने का कार्य दिया गया है। उन्हें कुल विक्री का 20 प्रतिशत मुनाफा दिया जा रहा है। इस कार्य में किसान रुचि दिखा रहे हैं। हमारे अलीपुर खेड़ा के माडल गोशाला में 5 लाख रुपये की खाद तैयार है। इसके बाद हम गोमूत्र की विक्री पर फोकस कर रहे हैं। गोमूत्र खरीदने वाली कंपनियों से बात हो गई है। जल्द ही यह काम

शुरू हो जाएगा। भूसा हमें किसानों से दान के रूप में मिल जाता है। हरा चारा निर्धारित चरागाहों में मनरेगा के जरिए पैदा कर लेते हैं। इस तरह से जनपद में गोशालाएं सरकार पर बोझ नहीं बल्कि लाभ में चल रही हैं।

एक मुलाकात में मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मैनपुरी प्रदेश का अकेला जिला है, जहां काला गेहूं पैदा किया जा रहा है। यह ग्लूटेन फ्री होता है। सुपाच्य है। पोषक तत्वों से भरपूर है। बाजार में काले गेहूं की भारी मांग है। इसका सर्टिफिकेशन हमने करा लिया है। ब्रांडिंग का कार्य शुरू कर दिए हैं। इससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है।

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए साइंस टेक लैब और स्पेस लैब बनाये जा रहे हैं। स्पेस लैब के सभी जरूरी सामान इसरो से मंगाए गए हैं। जुलाई के अंत



## काले गेहूं का बढ़ा रकबा, बढ़ी किसानों की आमदनी

मैनपुरी जिले में किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए अब प्रशासन काले गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देगा। स्वास्थ्य के लिए बेहतर माने जाने वाले काले गेहूं की कीमत अधिक होने से किसानों को लाभ भी अधिक होगा। इसके लिए कृषि विभाग और उद्योग विभाग ने संयुक्त रूप से कार्य शुरू कर दिया है। पहले चरण में काले गेहूं की बुवाई का रकबा बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी विनोद कुमार ने बताया कि कृषि प्रधान जिला होने के चलते मैनपुरी में गेहूं और धान का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है। मैनपुरी से बासमती चावल का निर्यात जहां यूरोपीय देशों के साथ ही खाड़ी देशों को होता है तो वहीं देशभर में इसकी मांग है। इससे किसानों को बासमती धान की कीमत भी बेहतर मिलती है। इसी के चलते अब कृषि विभाग और उद्योग विभाग ने किसानों की आय और बढ़ाने के लिए काले गेहूं की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

इसके तहत प्रचार-प्रसार करके कृषि विभाग पहले चरण में काले गेहूं का रकबा बढ़ाने में जुट गया है। इसके तहत कृषि विभाग के कर्मचारी और अधिकारी किसानों को काले गेहूं के प्रति जागरूक करेंगे। विभाग का मानना है कि किसान काला गेहूं इसलिए नहीं उगाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके उत्पादन की विधि सामान्य गेहूं से भिन्न है। वहीं कृषि विभाग के अनुसार ये एक मिथ्या बात है। सामान्य गेहूं की तरह ही आसानी से काले गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है।

कृषि विभाग का दावा है कि काले गेहूं के उत्पादन से किसानों की आय दोगुनी होना तय है। अगर किसान काला गेहूं उगाते हैं तो इसका निर्यात भी किया जाएगा। इससे कीमतें और भी अच्छी मिलेंगी। किसानों की राहत के लिए कृषि विभाग और उद्योग विभाग मिलकर मिलर्स से अनुबंध कराने के लिए भी तैयार हैं, ताकि बाद में किसानों को परेशान न होना पड़े। अधिक जानकारी के लिए किसान विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

कृषि विभाग के अनुसार काला गेहूं उगाने पर किसानों को दोगुना लाभ होगा। विभाग द्वारा तैयार एक चार्ट के अनुसार काले गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर 35 कुंतल के करीब होता है। अगर चार हजार रुपये प्रति कुंतल की दर से भी जोड़े तो ये लगभग 1.40 लाख रुपये का उत्पादन देता है। जो आमतौर पर एक हेक्टेयर में पैदा होने



वाले सफेद गेहूं की कीमत से दोगुना है। सफेद गेहूं का उत्पादन एक हेक्टेयर में औसतन 40 कुंतल होता है। इसकी कीमत 1800 रुपये से दो हजार रुपये प्रति कुंतल रहती है।

काले गेहूं के प्रति धीरे-धीरे किसानों में रुचि बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि बीते तीन सालों में काले गेहूं का रकबा शून्य से 75 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 में इसका क्षेत्रफल दो हेक्टेयर, 2021 में पांच हेक्टेयर था। जो 2022 में बढ़कर 75 हेक्टेयर पहुंच गया है।

### एंथोसाइनिन की अधिकता बनाती है खास

काले गेहूं में उपलब्ध एंथोसाइनिन नाम के पदार्थ की मात्रा की अधिकता उसे खास बनाती है। साथ ही अन्य पोषक तत्व भी सफेद गेहूं की तुलना में काले गेहूं में अधिक होते हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार काले गेहूं में सफेद गेहूं की तुलना में एंथोसाइनिन की मात्रा से 20 से लेकर 30 गुना तक, आयरन की मात्रा 20 प्रतिशत अधिक और जिंक की मात्रा 25 प्रतिशत तक अधिक होती है। काला गेहूं उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसके उत्पादन की विधि भी सामान्य गेहूं की समान ही है। लेकिन काले गेहूं की कीमत सामान्य गेहूं की अपेक्षा दोगुनी है, जिससे किसानों को लाभ भी दोगुना होगा।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि कृषि विभाग से जुड़कर काले गेहूं का उत्पादन जिले में बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर बड़े पैमाने पर जिले में काला गेहूं उत्पादन किया जाएगा, तो उसका निर्यात भी हो सकेगा, जिससे कीमत और भी बेहतर मिलेगी।

तक लैब का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें विद्यार्थी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम सहित अंतरिक्ष के तमाम रहस्यों के बारे में जान पाएंगे। यह प्रदेश का दूसरा स्पेस लैब होगा।

एडीएम सहारनपुर के रूप में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि वहां माफिया के रूप में हाजी इकबाल का दबदबा था। उनके अवैध कार्यों पर सख्ती से रोक लगाई। गलत तरीके से आम आदमी की कब्जा की गई जमीन को मुक्त

कराया। उन्होंने अवैध कार्यों के एवज में 250 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया। इसके अलावा मात्र एक महीने के रिकार्ड अवधि में भू अधिग्रहण कर सरसावां एयरपोर्ट के टर्मिनल निर्माण का रास्ता साफ किया। एयर स्ट्रिप का निर्माण कराया।

जनप्रतिनिधियों के दबाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि अपनी आइडेंटिटी बनानी पड़ती है। जन प्रतिनिधि पोलिटिकल बास होता है, लेकिन एक

ड्राफ्टेड नियम है। हमें उस नियम के दायरे में कार्य करने पड़ते हैं। किसी भी दशा में नियमों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है।

संतुष्टि कब मिलती है? पूछने पर उन्होंने बताया कि जब हम जन समस्याओं का निदान करते हैं। आम जन आकर धन्यवाद देता है, तो बहुत संतुष्टि की अनुभूति होती है। एसडीएम राम सनेही घाट, बाराबंकी की तैनाती के दौरान एक घटना का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि एल्लिगन बांध के जल भराव को रोकने के लिए



रामनगर में झूठी लगाई गई थी। रात में भी वहीं रहकर निगरानी करते थे और गांव वालों को बाढ़ के पानी से बचाते थे। उस समय कई गांव डूबने से बच गए। उन्होंने कहा कि जब उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया था, एक दिन एक बूढ़ा आदमी घर पर आया। उसके हाथ में आधा किलो घी का डिब्बा था। वह तैर कर नदी पार करके आया था। वह आभार स्वरूप घी भेंट करना चाहता था। मैं उसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। पिता जी ने सीख दी, बेदा घी के डिब्बे को मत देखो, उसके भाव को समझो। तुमने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गांव को डूबने से बचाया है। इसके लिए वह गांव की ओर से कृतज्ञता प्रकट करना चाहता है।

कानून व्यवस्था की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि जब वह लखनऊ में सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो आये दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया। लक्ष्मण मैदान से बंदरिया बाग चौराहे तक कांग्रेस का प्रदर्शन जुलूस निकल रहा था। भारी हुजूम को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई थी। अचानक एक पत्थर आकर उनके चश्मे के शीशे को तोड़ता हुआ, आंख में घुस गया। खून की धारा बहने लगी। बेहोशी की हालत में गिर गए। सिविल अस्पताल ले जाया गया। आपरेशन से पत्थर के टुकड़े

## कहां-कहां रहे तैनात

डिप्टी कलेक्टर	- गाजीपुर, शाहजहांपुर, बाराबंकी और लखनऊ।
सिटी मजिस्ट्रेट	- लखनऊ।
अपर नगर आयुक्त	- लखनऊ।
अपर जिलाधिकारी	- अयोध्या।
उप निदेशक मंडी	- लखनऊ।
अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)	- सहारनपुर।
मुख्य विकास अधिकारी	- मैनपुरी।

निकले गए। ठीक होने में काफी समय लगा, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे।

सेवा में आने के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा डाक्टर बनने की थी। लेकिन फिजिक्स कमजोर थी। बीएएमएस में चयन भी हुआ। पढ़ने के लिए वाराणसी से इलाहाबाद (वर्तमान काशी, प्रयागराज) आ गए। इलाहाबाद में बड़ा आसमान मिला। विश्वविद्यालय से एलएलएम की परीक्षा पास की। वह पहले फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे। यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल के अलावा उन्हें वाईस चांसलर गोल्ड मेडल भी मिला। वर्ष 2002 में पीसीएस में चयनित होने के पहले सहकारिता विभाग के आडिटर पद पर चयन हुआ था। यूको बैंक में लॉ अफसर भी रहे। 2004 बैच मिलने के बाद गाजीपुर,

शाहजहांपुर, बाराबंकी में एसडीएम के पद पर रहे। लखनऊ में नगर मजिस्ट्रेट, ज्वाइंट डायरेक्टर मंडी पद पर तैनात रहे। अयोध्या और सहारनपुर में एडीएम के पद पर तैनाती के बाद मैनपुरी के सीडीओ बनाये गए।

पीसीएस बनने की तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के बारे में उनका संदेश है There is no short cut than hard work for success in life. यह सूत्र मेरे गुरु ने दिया था। आज भी मैं इसी सूत्र के सहारे जन सेवा करता हूं। आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं होती है। ईश्वर सर्वव्यापी है। कर्म ही आपकी पहचान बनाती है। कर्तव्य पथ से कभी विचलित न हों। □



यमुना एक्सप्रेस-वे औ.वि. प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा विगत 11 अगस्त को ग्राम उस्मानपुर में प्राधिकरण द्वारा कैप लगाकर 11 किसानों को अतिरिक्त प्रतिकर की मद में 1 करोड़ 93 लाख 94,471/- रुपये का भुगतान किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार विपिन कुमार समेत भूलेख विभाग व परियोजना विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।



टी.बी. सिंह  
9415000151



**इ**स अविश्वास प्रस्ताव का अंजाम क्या होगा यह सभी को पता था। लेकिन यह नहीं पता था कि इसका हस कुछ इस तरह होगा कि मामला वॉकओवर जैसा दिखने लगा। क्योंकि मत

विभाजन तो हुआ ही नहीं। फिर कैसे पता चलता कि कौन किसके पाले में खड़ा है? पूरा विपक्ष बहिर्गमन कर गया।

विपक्ष के नेता का यह कहना कि अविश्वास प्रस्ताव की ताकत प्रधानमंत्री को संसद में ले आई है। लेकिन जब प्रधानमंत्री संसद में आए और अपनी बात कही तो विपक्ष को उनकी बात सुननी भी चाहिए थी। लेकिन तब विपक्ष गायब था और ध्वनिमत ने अविश्वास प्रस्ताव अपने अंजाम पर पहुंच गया। क्या विपक्ष प्रधानमंत्री को केवल संसद में लाने के लिए ही यह अविश्वास प्रस्ताव लाया था? इससे तो मणिपुर की समस्या कहां समाधान की ओर जाती है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी रौ में इस तरह बहक गए कि उन्हें संस्पेंड होने का दंश तक झेलना पड़ा। यह भी विपक्ष के लिए एक झटका ही साबित हुआ है।

यह भी सच है कि 'अविश्वास' नहीं टिका

लेकिन जुबानी तीर खूब चले। तीन दिवसीय बहस में पक्ष-विपक्ष ने एक दूसरे को घेरने में पूरी ताकत लगा दी। इससे संसद के अंदर से लेकर बाहर तक सियासी माहौल जरूर गर्म रहा। बावजूद इसके यह कहना कहीं ज्यादा सही होगा कि मुद्दों के बजाय तीन दिन चली बहस में एक-दूसरे पर व्यक्तिगत कटाक्ष ज्यादा किए गए। इस दौरान असंसदीय भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। प्रतिपक्ष के नेता अधीर रंजन मोदी पर टिप्पणी करने के चलते ही संस्पेंड हुए। मुद्दों से हटने के साथ ही अन्य मोर्चे पर भी विपक्ष सत्तापक्ष से पिछड़ा रहा। इस दौरान सत्तापक्ष की जहां मजबूती नजर आयी वहीं विपक्ष की कमजोरी उजागर हुई। यह जरूर हुआ कि विपक्ष अपने प्रस्ताव के जरिए प्रधानमंत्री को मणिपुर पर जवाब देने के लिए विवश कर सका लेकिन मंहगाई जैसे मुद्दे पर वह सरकार को घेरने में असफल रहा। तीन दिन की बहस में



चुनावी राजनीति भारी रही। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस मौके का फायदा उठाया। उन्होंने न केवल जमकर पलटवार करते हुए उनके सभी भाषण ही दिया बल्कि विपक्ष पर आरोपों को खारिज कर दिया। पूरी तरह हमलावर होकर प्रधानमंत्री ने अपने लंबे भाषण

### मणिपुर पर राजनीति न करें : शाह

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान कहा कि मैं विपक्ष की बात से सहमत हूँ कि मणिपुर में हिंसा हुई है। निश्चय ही ये घटनाएं शर्मनाक हैं। लेकिन उन पर राजनीति करना और भी शर्मनाक है। शाह ने सरकार की ओर से सबसे मजबूत ढंग से मणिपुर के हालातों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं।

मास्टर स्ट्रोक चलते हुए उन्होंने सदन में शांति बनाए रखने का प्रस्ताव रखा। जिसे विपक्ष सहित सत्ता पक्ष ने भी समर्थन देते हुए ध्वनिमत से पास कर दिया।

### मणिपुर को बांट दिया : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है।

उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह रावण सिर्फ दो लोगों की बात सुनता था ठीक उसी तरह मोदी भी दो लोगों की सुनते हैं - अमित शाह और अडाणी। भारत एक आवाज है। अगर इस आवाज को सुनना है तो आपको अहंकार और नफरत को छोड़ना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हरिणाया समेत पूरे देश में मिट्टी का तेल फेंक रही है। पीएम पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। जबकि राहुल ने मणिपुर की महिलाओं के अनुभव सुनाए जो दिल को छूने वाले थे। दूसरी ओर उन्होंने भाजपा की भाषा में ही उन्हें करारा जवाब दिया।

### कांग्रेस का इतिहास खून से सना : स्मृति

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उनको भारता माता संबंधी बयान पर घेरा। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में यह पहली बार है कि किसी ने भारत मां को लेकर ऐसी बात कही। और कांग्रेस नेताओं ने इस पर तालियां बजायीं। यह बताता है कि देश को लेकर किसके मन में गद्दारी है।

उन्होंने आपातकाल, सिक्ख दंगों, कश्मीरी पंडितों की हत्या और भीलवाड़ा में 14 साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा इतिहास खून से सना है।

स्मृति ईरानी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि मणिपुर न खंडित है, न विभाजित है, वह देश का हिस्सा है। विपक्षी गठबंधन के एक सदस्य ने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब केवल उत्तर भारत है। राहुल गांधी में हिम्मत है तो खंडन करके बताएं।





में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को पूरी तरह निशाने पर रखा। उन्होंने विपक्ष के रवैये और आचरण की तीखी आलोचना की। साथ ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंशा, नीति एवं नियत पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने मणिपुर के हालात पर चर्चा के साथ ही पूर्वोत्तर को लेकर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी बताई। साथ ही 2024 में फिर भारी बहुमत से सत्ता में आने का विश्वास भी जता दिया।

कई अवसरों पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि इस चर्चा में मजा तो तब आया जब फिलिडिंग विपक्ष ने लगाई लेकिन चौके-छक्के हमारे ही तरफ से लगे। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर नो बाल ही करता नजर आया और हमारी तरफ से सभी शतक लगाते रहे।

मणिपुर की चर्चा करते हुए उन्होंने जहां मणिपुर को देश के जिगर का टुकड़ा बताया तो वहीं यह भी कहा कि राज्य में शांति का सूरज फिर से उगेगा। महिलाओं के साथ हुए अपराध को अक्षम्य बताते हुए कहा कि पूरा देश मणिपुर की माताओं, बहनों और बेटीयों के साथ है। राहुल से लेकर विपक्षी गठबंधन तक उन्होंने किसी को भी नहीं बख्शा। बिना नाम लिए राहुल पर तंज कसा। कांग्रेस की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि वर्षों से वे बार-बार एक असफल उत्पाद लांच करते रहे। हर बार लांचिंग फेल हो जाती है। नतीजा यह है कि मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं विपक्ष के साथ सहानुभूति जताना चाहता हूं क्योंकि कुछ दिन पहले आप ने बैंगलूरु में यूपीए का अंतिम संस्कार किया। एक ओर आप अंतिम संस्कार कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे और जश्न भी किस बात का। खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का।

विपक्ष के वॉक आउट पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह सुनाने के लिए तो तैयार रहते हैं पर उनमें सुनने का धैर्य नहीं होता। अविश्वास प्रस्ताव पर इन्होंने हर विषय पर बोला। हमने कहा था अकेले मणिपुर पर आओ। लेकिन साहस नहीं था। सिवाय राजनीति के इन्हें कुछ नहीं करना है। आज भी भाग गए।

अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ है और यह विपक्ष के लिए शक्ति परीक्षण। उन्होंने कांग्रेस पर हर तरफ से निशाना साधा। राहुल गांधी के लंका वाले बयान पर वह बोले कि कई बार बुरा बोलने के इरादे में भी सच निकल जाता है। लंका हनुमान ने नहीं जलाई रावण के घमंड ने जलाई, इसलिए 400 से 40 (कांग्रेस के)



### यह था 28वां अविश्वास प्रस्ताव

मोदी सरकार के खिलाफ इस बार संसद में लाया गया यह इतिहास का 28वां अविश्वास प्रस्ताव था।

केवल इस बार ही नहीं बल्कि इसके पहले लाए गए सभी अविश्वास प्रस्तावों पर कभी भी सरकार नहीं गिरी। अब तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्तावों में 15 प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ थे।

जहां तक पहले अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो चीन के खिलाफ 1962 के युद्ध में मिली पराजय के बाद अगस्त 1963 में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू सरकार के खिलाफ जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। अभी तक तीन बार विश्वास मत में सरकार गिरी है।

सांसद हो गए हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हुए विश्वास से भरे नजर आने के साथ ही बोले कि विपक्ष 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी करे।

उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में उसके खिलाफ लाया गया यह एक मात्र अविश्वास प्रस्ताव था। जबकि इसके पहले पिछले कार्यकाल में भी एक बार ही 2018 में

लाया गया था।

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए असम से कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर में हिंसा रोकने में डबल इंजन सरकार पूरी तरह विफल रही। विपक्ष को मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। जिससे इस मामले पर पीएम का मौनव्रत तोड़ा जा सके। वैसे पहले यह सोचा जा रहा था कि राहुल गांधी ने पूर्वोत्तर के सांसद से बहस शुरू कराकर मास्टर स्ट्रोक खेल लिया। गोगोई के अलावा विपक्ष की ओर से एनसीपी की सुप्रिया सुले ने भी भाषण दिया। लेकिन वह मुद्दे से हटकर इधर-उधर की बातें ही करती रहीं।

पहले दिन भाजपा सांसदों ने विपक्ष की पिच पर न खेलते हुए विपक्षी गठबंधन को घेरने की कोशिश की। भाजपा सांसद निशीकांत दुबे ने कहा कि विपक्षी गठबंधन एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। लेकिन नाम इंडिया रखा है। यह अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ लाया गया है। यह प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने गरीबों को मकान बनाकर दिए, जिसने गरीब जनता को पीने का पानी दिया, शौचालय दिए, जिसने गरीब के घर में उजाला लाने की कोशिश की। वहीं केन्द्रिय मंत्री किरण रिजिजू ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस इस प्रस्ताव को लाने के लिए बाद में पछताएंगे। □



गोविन्द पंत राजू  
9415014980



माचल प्रदेश में जुलाई के महीने में मंडी इलाके में हुई भीषण तबाही और बाढ़ जैसी स्थितियों के जख्म जरा भरे भी नहीं थे कि उत्तराखंड में टनकपुर से लेकर देहरादून तक तराई और भाबर के इलाके में अगस्त की शुरुआत से हो रही भीषण बारिश ने नई तबाहियां पैदा करनी शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश - हरिद्वार और देहरादून - विकासनगर तक तमाम इलाकों में अनेक पुल टूट गए हैं, दर्जनों लोगों की मौतें हुई हैं और

सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। तमाम मोटर रोडों का बुरा हाल हो गया है। अनेक छोटी बड़ी नदियां और छोटे-छोटे गंधेयों ने अपने प्रवाह के चलते इस संकट को और तीव्र बना दिया है।

यों तो पिछले कुछ वर्षों से बरसात का मौसम पहाड़ी इलाकों में तबाही लाता रहा है लेकिन अब यह तबाही बरसात के मौसम के अलावा अन्य मौसमों में होने वाली वर्षा के दौरान भी होने लगी है। 5000 से ज्यादा लोगों की जान लेने और अरबों रुपए की संपत्ति लील लेने वाली 2013 की केदारनाथ आपदा जून के महीने में आई थी और चमोली जिले में 2021 की धौलीगंगा घाटी में 200 से ज्यादा लोगों को शिकार बनाने तथा दो बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का सफाया करने वाली तबाही फरवरी के महीने में हुई थी।

साफ दिखता है कि अब आपदा का संबंध सिर्फ मानसून के साथ ही नहीं रह गया है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे नए कारक भी तबाहियों की संख्या एवम विनाशकारी क्षमता को बढ़ाने में सहायक होने लगे हैं। लेकिन अगर गंभीरता से देखा जाए तो यह समझ में आता है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में बढ़ती जा रही इन आपदाओं के लिए मानवीय गतिविधियां भी बहुत जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड की केदारनाथ आपदा और चमोली की विष्णुप्रयाग तबाही मुख्य रूप से मानवजनित

कारणों से ही हुई थी। इसी तरह उत्तराखंड के सबसे पुराने शहर जोशीमठ की बर्बादी के पीछे भी मुख्य वजह यही है। उत्तराखंड में इन आपदाओं की वजहें जितनी प्राकृतिक हैं उससे अधिक मानवजन्य हैं। यह मानवीय हस्तक्षेप दो तरह का है।

एक स्थानीय लोगों के द्वारा प्रकृति के खिलाफ की जा रही गतिविधियां और दूसरी सरकारी स्तर पर चलाई जा रही तथाकथित विकास गतिविधियां। आपदाओं को बढ़ाने में इस तरह की विकास गतिविधियों का योगदान स्थानीय आबादी के द्वारा किए जा रहे नुकसान का 8 से 10 गुना अधिक है। उत्तराखंड के संदर्भ में इस तरह की विकास योजनाएं आल वेदर रोड और रेल परियोजनाओं के साथ-साथ छोटी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं, बांध और उनके लिए खोदी जाने वाली सुरंगों विकास के नाम पर तबाही बढ़ाने का काम कर रही हैं।

भूगर्भीय दृष्टि से अस्थिर माने जाने वाले उत्तराखंड में बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं ने पर्वतीय क्षेत्रों को भीतर से कमजोर बनाया है। भूजल के प्राकृतिक प्रवाह को भी क्षत विक्षत कर दिया है। इन्होंने बड़े पैमाने पर बायो डायवर्सिटी को नष्ट किया है और वन संपदा को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया है। उत्तराखंड की बहु प्रचारित आल वेदर रोड के लिए ही तमाम नियम कानूनों को धता बताकर





हजारों की संख्या में हिमालय क्षेत्र के देवदार आदि के वृक्षों को काट दिया गया था। जिसकी भरपाई अब किसी भी दशा में नए पेड़ लगाकर की ही नहीं जा सकती। जोशीमठ का धंसाव इस तरह के विनाश का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बाई पास और विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना के लिए खोजी जाने वाली टनलों ने किस तरह पूरे जोशीमठ शहर को हिला कर रख दिया है।

हिमाचल प्रदेश में पिछले महीने हुई भीषण तबाही के लिए भी कुछ इसी तरह की वजहें सामने आई हैं। हालांकि वहां पर तथाकथित विकास परियोजनाओं की तुलना में स्थानीय मानव जनित गतिविधियां तबाही के लिए अधिक जिम्मेदार समझी जा रही हैं।

प्रसिद्ध विज्ञानी और भूगर्भवेत्ता डा. नवीन जुयाल अभी हिमाचल के आपदा प्रभावित इलाकों से आपदा के कारणों का अध्ययन कर वापस लौटे हैं। उनका मानना है कि हिमाचल में स्थानीय लोगों ने बढ़ती पर्यटक गतिविधियों के चलते जिस तरह नदियों, छोटे-छोटे नालों और गंधेयों के प्राकृतिक प्रवाह के भीतर घुसकर निर्माण कार्य किए थे उस ने ही आपदा को कई गुना बढ़ाया है। डा. जुयाल ने केदारनाथ और विष्णुप्रयाग तबाहियों के कारणों का भी अध्ययन किया था। इसलिए वे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की आपदाओं की प्रमुख वजहों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए दोनों के बीच में यह अंतर रेखांकित कर पा रहे हैं।

हिमाचल में जुलाई में हुई तबाही में 150 से ज्यादा जानें गई और 10 हजार करोड़ रुपए

से अधिक की संपत्ति बर्बाद हुई थी। पर्यावरण विशेषज्ञ मानते हैं कि देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश की वजह से हुई बर्बादी अप्रत्याशित नहीं है। पिछले कई दशकों में पर्यटन के केंद्र इस पहाड़ी राज्य ने विकास के मामले में मैदानी इलाकों की राह पर चलने की कोशिशें की हैं और स्पष्ट रूप से इसका नतीजा प्राकृतिक आपदाओं में दिख रहा है।

चाहे कमजोर पहाड़ों में चार लेन हाइवे निकालना हो या हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंगें खोदना। इन सबने पहाड़ और पथरों को हिला दिया है। भारी, बेतरतीब और असुरक्षित निर्माण हर जगह हो रहा है और निर्माण का कचरा नदियों और उनकी शाखाओं तक पहुंच रहा है। इन सबने मिलकर बारिश की तबाही को और भी बढ़ा दिया है। हिमाचल प्रदेश में नदियों से कथित अवैज्ञानिक खनन ने भी ऐसी आपदाओं का खतरा बढ़ने की चिंताएं बढ़ा दी हैं।

पर्यावरणविदों को लगता है कि हिमाचल प्रदेश में उफनाई नदियों, खासकर ब्यास की वजह से हुई भारी तबाही का एक कारण मोटे तौर पर स्पष्ट है और इसकी तुलना साल 2000 में सतलुज नदी में आई बाढ़ से की जा सकती है। तब रामपुर शहर में इससे भारी तबाही हुई थी, वहां बहुत से लोग नदी के पास बने निर्माणों में रह रहे थे। ब्यास नदी की घाटी में भी, निर्माण नदी के बेहद आसपास तक पहुंच गया है, ऐसे में अचानक आई बाढ़ से नुकसान का खतरा और अधिक बढ़ जाता है।

वास्तव में इस बार ऐसा ही हुआ भी। ब्यास में तेज गति से आ रहे पानी ने रास्ता बदला और मनाली से मंडी के बीच बहुत से मकान, वाहन, जानवर और कई जगहों पर राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्से बह गए। वैसे भी, ब्यास की रफ्तार इस क्षेत्र में तेज होती है और पानी सड़क से बहुत दूर नहीं होता है।

पर्यावरण विशेषज्ञ संजय सहगल कहते हैं, “अब समय आ गया है जब हम पर्यटन पर चलने वाले इस राज्य में विकास का ऐसा माडल अपनाएं जो पर्यावरण के अनुरूप हो। हम एक सीमा के बाद प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। सीमा लांघने के बाद प्रकृति स्वयं अपनी सीमाएं निर्मित करने लगती है। अवैज्ञानिक रूप से विकास कार्यों के लिए पहाड़ों में विस्फोट और निर्माण कार्यों के मलबे को बिना योजना के डंप करने और अनियंत्रित संख्या में वाहनों के पहाड़ी सड़कों पर चलने के दुष्परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। हम इसका अहसास नहीं कर पा रहे हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के 2017 में हुए एक शोध से पता चला था कि हिमाचल प्रदेश में कुल 118 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं जिनमें से 67 पहाड़ खिसकने वाले इलाकों में हैं।

राज्य के आदिवासी बहुल जिले किन्नौर, कुल्ली और कई अलग हिस्सों में जब हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाये जा रहे थे तब पर्यावरणविदों और प्रभावित स्थानीय नागरिकों ने उनका विरोध भी किया था और कई जन अभियान भी चले थे। लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी राजनीतिक दलों ने



इन्हें नजरअंदाज कर दिया था। चिपको आंदोलन का हिस्सा रहे अभिमन्यु कहते हैं, “समय आ गया है जब हम प्रकृति के इस आक्रोश से सबक लें, इस संवेदनशील पर्यावरण और इस बात को समझने का प्रयास करें कि परिस्थितिकी रूप से नाजुक इस क्षेत्र में पर्यावरण की कीमत पर हो रहे असंतुलित विकास की वजह से प्रकृति का कोप बढ़ रहा है।” अभिमन्यु कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है और लोग यहां प्राकृतिक सुंदरता को देखने आते हैं।

वो सवाल करते हैं, “देखो, हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अपने खूबसूरत पहाड़ों के साथ क्या कर रहे हैं? यह समझना चाहिए कि इसके बदले में प्रकृति भी हमारे लिए खतरनाक होती जा रही है। हमें चार लेन वाली सड़कों की जरूरत क्यों हैं, बड़े बांकागत या हाइड्रो प्रोजेक्ट हमें क्यों चाहिए जो पहाड़ों को भीतर से खोखला कर रहे हैं? हम ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पहाड़ों और नदियों की वहन क्षमता का अध्ययन क्यों नहीं करते हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके?”

वास्तव में आज पूरे हिमालय से जुड़े क्षेत्रों के लिए विकास की नई अवधारणा बहुत जरूरी है क्योंकि आज जिस तरह का विकास हो रहा है, वह समूचे हिमालय क्षेत्र के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। यदि उस भूगर्भीय और भौगोलिक रूप से अतिसंवेदनशील इलाके में प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा और स्थितियां मानव वास के अनुकूल नहीं रह

जाएंगी, तब फिर ऐसे विकास के क्या मायने रह जाएंगे? उत्तराखंड ने पहली चेतावनी दे दी थी और अब हिमाचल प्रदेश में दूसरी चेतावनी दे दी है इसलिए अब वक्त आ गया है कि हमारे योजनाकार और विकास की बातें करने वाले राजनेता बहुत गंभीर होकर उत्तराखंड और हिमालय की परिस्थितियों के अनुकूल विकास योजनाओं के बारे में सोचने लगें तथा उसी के अनुकूल विकास योजनाओं को बनाया और चलाया भी जाए।

अब वक्त आ गया है हमें अपने विकास माडल पर पुनर्विचार करना चाहिए। बांधों और बड़ी परियोजनाओं के निर्माण के तरीके में बदलाव, फसल और बागवानी तथा वनीकरण के पैटर्न में परिवर्तन के साथ-साथ पर्यटन की भीड़ की समस्या के वास्तविक समाधान के बारे में नए सिरे से सोचा जाना चाहिए। यह सही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सामान्य वर्षा का औसत लगातार बढ़ रहा है और जिन इलाकों में 500-600 मिलीमीटर वर्षा हुआ करती थी वहां अब 750 मिमी से 900 मिली मीटर तक बारिश होने लगी है। इसमें भी चिंता करने वाली बात यह है अनेक बार बहुत कम वक्त में बहुत तेज बारिश हो जाती है और वह बादल फटने आदि रूपों में विनाशकारी प्रभाव लेकर आती है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि हमने हिमालय क्षेत्र के विकास के लिए जिन चीजों को संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया है उनमें वन, जल और पर्यटन प्रमुख रहे हैं।

गौरतलब है कि हाल के वर्षों में इन इलाकों में आने वाली आपदाओं के लिए प्रमुख रूप से यह तीन संसाधन की किसी न किसी रूप में जिम्मेदार रहे हैं। अकेले हिमाचल प्रदेश में ही इस वक्त 168 जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं और लगभग 11000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। निकट भविष्य में यह उत्पादन दुगुने से अधिक किए जाने की योजना है और इसके लिए लगभग 1000 जल विद्युत योजनाएं या तो विचाराधीन हैं या उन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

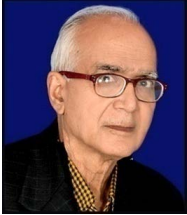
इन योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर सुरंगें खोदी जाती हैं और नदियों के प्राकृतिक जल प्रवाह क्षेत्र को बुरी तरह क्षति पहुंचाई जाती है। इन परियोजनाओं के निर्माण से पैदा होने वाला मलवा, मिट्टी, पत्थर आदि इन्हीं नदियों में डाल दिया जाता है, जो आगे चलकर बड़ी तबाही यों की वजह बनता है। यही हाल सड़क चौड़ीकरण योजनाओं का भी है। इसके लिए पहाड़ों को बुरी तरह से काटा और छीला जाता है, जिसके बाद हल्की सी बारिश भी बड़े भूस्खलनों को जन्म देती है। यही भूस्खलन पर्वतीय इलाकों में नासूर की तरह बन जाते हैं।

यह सोचा जाना चाहिए कि अगर हिमालयी क्षेत्र अस्थिर होगा तो इसका सीधा दुष्प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार की आबादी के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ेगा। समस्या बहुत बड़ी है और इसीलिए इसका समाधान भी बड़ा ही होना जरूरी है। □



**डॉ. नवनीत सहगल  
हुए रिवायर**

# अब बुढ़ापे पर लगोगी लगाम



निरंकार सिंह  
9451910615



## मृ

त्यु पर विजय मानव सभ्यता का अन्तिम लक्ष्य है और अमरत्व मानव प्रजाति की चरम नियति। विज्ञान ने अब ऐसी प्रक्रियाओं के दरवाजे खोल दिये हैं जिनके जरिये हम अमर भले न हो सकें परन्तु लंबे, खूब लंबे समय तक जवान और जिंदा रह सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, नैनो, सूचना और तंत्रिका विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से काम हो रहा है, नित नई खोजें हो रही हैं। इससे यह संभावना आकार ले रही है कि भविष्य में मानव आयु लम्बी हो सकती है। बुढ़ापे को रोक देने वाली दवा, उम्र को और अधिक बढ़ा देने वाले नये उपचार और दीर्घजीविता अथवा लॉगविटी क्लिनिक इत्यादि इसकी झलक है। बर्मिंघम के एस्टन रिसर्च सेंटर फार हेल्थी एजिंग की सीनियर लेक्चरर कैथी स्लैक के अनुसार बुढ़ापा एक नितांत निजी प्रक्रिया है। किन्हीं भी दो लोगों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक सी नहीं होती है। हम बूढ़े क्यों होते हैं और क्या इस जैविक प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा है।

हार्वर्ड में जेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख वैज्ञानिक डेविड ए. सिंकलेयर ने कहा, 'हाल ही तक, हम जो सबसे अच्छा काम कर सकते थे, वह धीमी गति से उम्र बढ़ना था। नई खोजों से पता चलता है कि अब हम इसे



उलट सकते हैं।' अमेरिकी शोधकर्ताओं ने एक अभूतपूर्व अध्ययन में बुढ़ापा और बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने कोशिकाओं को युवा अवस्था में पुनः प्रोग्राम करने वाले रसायनों की खोज की है। पहले, यह केवल शक्तिशाली जीन थेरेपी का उपयोग करके ही संभव था।

जर्नल एजिंग-यूएस में प्रकाशित निष्कर्ष, इस खोज पर आधारित है कि विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति, जिसे यामानाका कारक कहा जाता है। वयस्क कोशिकाओं को प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल (आईपीएससी) में परिवर्तित कर सकती है। इस खोज ने -जिसने 2012 में नोबेल पुरस्कार जीता,- यह सवाल उठाया कि क्या कोशिकाओं को बहुत युवा और कैसरग्रस्त बनाए बिना सेलुलर उम्र बढ़ने को उलटना संभव हो सकता है। शोधकर्ताओं ने सेलुलर उम्र बढ़ने को उलटने के लिए एक रासायनिक विधि का उपयोग करके उम्र को उलटने में एक सफलता

हासिल की है। उनके अध्ययन ने छह रासायनिक संयोजनों की पहचान की, जो अनियमित कोशिका वृद्धि के बिना एक सप्ताह के भीतर वृद्ध कोशिकाओं को फिर से जीवंत कर देते हैं।

डा. डेविड ए. सिंकलेयर के नेतृत्व में, जे-ह्यून यांग, क्रिस्टोफर सहित शोधकर्ताओं की टीम ए. पेटी और मारिया वीना लोपेज ने आनुवंशिक हेरफेर के बजाय रासायनिक हस्तक्षेप का उपयोग करके कोशिकाओं को फिर से जीवंत करने की संभावना का पता लगाया। इस अध्ययन में, वैज्ञानिकों का लक्ष्य ऐसे रासायनिक संयोजन ढूँढना था जो कोशिका सुरक्षा से समझौता किए बिना सेलुलर उम्र बढ़ने को उलट सके। उन्नत कोशिका-आधारित परीक्षणों और उम्र बढ़ने वाली घड़ियों का उपयोग करते हुए, टीम ने छह रासायनिक संयोजनों की पहचान की, जिन्होंने एक सप्ताह के भीतर वृद्ध कोशिकाओं में सफलतापूर्वक युवावस्था बहाल कर दी। उत्साहजनक रूप से, शोधकर्ताओं ने इन परिणामों को अनियमित कोशिका वृद्धि के बिना हासिल किया।

इस नई खोज के निहितार्थ दूरगामी हैं, जिससे नयी चिकित्सा और संभावित रूप से पूरे शरीर के कायाकल्प के रास्ते खुल रहे हैं। जिन थेरेपी के माध्यम से उम्र में बदलाव की जगह इस खोज ने एक रासायनिक विकल्प विकसित किया है। यह खोज उम्र बढ़ने, चोटों और उम्र से संबंधित बीमारियों के उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है और विकास में कम लागत और कम समयसीमा का रास्ता दिखाया है। अप्रैल 2023 में बंदरों में अंधापन को उलटने में सकारात्मक परिणामों के बाद उम्र पलटने वाली जिन थेरेपी के इंसानों पर क्लीनिकल परीक्षणों की तैयारी प्रगति पर है। हार्वर्ड की यह टीम एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती है जहां उम्र से संबंधित बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज किया जा सके। चोटों का अधिक कुशलता से उपचार किया जा सके और पूरे शरीर के कायाकल्प का सपना वास्तविकता बन सके। सिनक्लेयर ने कहा, 'यह नई खोज एक ही गोली से बुढ़ापे को उलटने की क्षमता प्रदान करती है, जिसमें आंखों की रोशनी में सुधार से लेकर उम्र से संबंधित कई बीमारियों का प्रभावी ढंग से इलाज करने तक के प्रयोग शामिल हैं।'

स्पेन में शोधकर्ताओं ने शरीर के भीतर होने वाली उन मुख्य प्रक्रियाओं का पता लगाया है, जो उम्र बढ़ने के साथ होती हैं। डा. मैनुअल सेरानो के अनुसार ये वे प्रक्रियाएं हैं जो निश्चित रूप से होती ही हैं। यह हर इंसान में कम या ज्यादा नजर आ सकती है और इसका सारा श्रेय हमारी लाइफस्टाइल और आनुवांशिकी को जाता है। लेकिन यह सतत रूप से होती रहती है। स्तनधारी जीवों में बढ़ती उम्र के साथ ये नौ लक्षण नजर आने लगते हैं, यही लक्षण इंसानों को भी एहसास दिलाते हैं कि वे बूढ़े होने लगे हैं। हमारा डीएनए एक तरह का जेनेटिक कोड होता है जो कोशिकाओं के बीच संचरित होता है। उम्र बढ़ने से इन जेनेटिक कोड के संचरण में गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे यह कोशिकाओं में जमा होना शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को आनुवांशिक अस्थिरता के रूप में जाना जाता है और यह विशेष रूप से तब प्रासंगिक होता है जब डीएनए स्टेम कोशिकाओं को प्रभावित करता है। आनुवांशिक अस्थिरता स्टेम कोशिकाओं की भूमिका को खतरे में डाल सकती है। अगर ये अस्थिरता बढ़ जाती है तो यह कैंसर में भी तब्दील हो सकती है।

हर डीएनए सूत्र के अंतिम छोर पर कैप

जैसी संरचना होती है जो हमारे क्रोमोसोम को सुरक्षित रखते हैं- ये बिल्कुल वैसी ही संरचना होती है, जैसे हमारे जूतों के फीतों की, जिसमें फीते के अंतिम छोर पर एक प्लास्टिक का टिप लगा होता है। इन्हें टेलोमर्स कहते हैं। हम जैसे-जैसे उम्रदराज होते जाते हैं, ये कैप रुपी संरचना हटने लगती है और क्रोमोसोम की सुरक्षा ढीली पड़ने लगती है। इस वजह से परेशानी पैदा हो सकती है।

शोधकर्ता मानते हैं कि टेलोमर्स की संरचना में जब गड़बड़ी आती है तो कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से फेफड़ों से जुड़ी समस्याएं और एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों ही रोग प्रतिरक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याएं हैं। हमारे शरीर



में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है, जिसे डीएनए एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें किसी एक कोशिका में मौजूद हजारों जीन्स ये तय करते हैं कि उस कोशिका को क्या करना है। मसलन, क्या उस कोशिका को त्वचा वाली कोशिका के तौर पर काम करना है या मस्तिष्क कोशिका के रूप में। लेकिन समय और जीवनशैली इन निर्देशों को बदल सकते हैं। ऐसे में कोशिकाएं भी अपने तय व्यवहार से अलग तरीके से व्यवहार कर सकती हैं।

हमारी कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त घटकों के संचय को रोकने के लिए शरीर में नवीनीकरण की क्षमता होती है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही ये क्षमता धीरे-धीरे कम होती जाती है। ऐसे में कोशिकाएं बेकार या जहरीले प्रोटीन जमा

करने लगती हैं- जो कई बार अल्जाइमर का कारण बन जाता है। कई बार इसकी वजह से पार्किन्संस और मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ जाता है। बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाएं वसा और शक्कर के तत्व को सोखने की क्षमता खोती जाती हैं। इसके चलते बहुत बार मधुमेह की शिकायत हो जाती है। बढ़ती उम्र में जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत होती है उन लोगों में विशेष रूप से यही कारण होता है- उम्रदराज शरीर उन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है जो वह खाता है। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है लेकिन समय के साथ ये अपनी क्षमता खोने लगते हैं। इनके कमजोर पड़ने से डीएनए पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। जून में विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुए एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वैज्ञानिकों ने माइटोकॉन्ड्रिया को री-स्टोर करके चूहों में झुर्रियों को दूर कर दिया।

जब कोई कोशिका बहुत अधिक चोटिल हो जाती है तो वह विघटित होना तो बंद हो जाती है लेकिन मरती नहीं है। ये जंम्बी सेल अपने आस-पास की कोशिकाओं को भी संक्रमित करने लगती है और इसके चलते पूरे शरीर में सूजन हो जाती है। ये कोशिकाएं उम्र और समय के साथ जमा होने लगती हैं। स्टेम सेल अपनी क्षमता खोने लगती हैं। उम्र बढ़ने के साथ कोशिकाओं की पुनरुत्पादक क्षमता में कमी आ जाती है। स्टेम कोशिकाएं थकने लगती हैं।

हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि स्टेम कोशिकाओं के कायाकल्प से बढ़ती उम्र के शारीरिक लक्षणों को सामने आने से रोका जा सकता है। कोशिकाएं हमेशा एक-दूसरे से संपर्क में रहती हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनका ये आपसी संपर्क घटने लग जाता है। उनके बीच संपर्क नहीं होने का असर ये होता है कि शरीर में सूजन आ जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि वे रोगजनक और घातक कोशिकाओं के प्रति सक्रिय नहीं रह जाती हैं।

सेरानो का कहना है कि भले ही यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता है लेकिन एक स्वस्थ जीवनशैली से इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। आज के समय में बुजुर्ग ज्यादा स्वस्थ और धनी हैं। जो सबसे बेहतर चीज हम कर सकते हैं वह यह कि हम अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं। □



# आभासी शांति का युद्धकाल



के. आर. विक्रम सिंह  
9415204212



**य**ह युद्धकाल नहीं है तो और क्या है ? नूंह मेवात में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए जो हुआ वह युद्ध ही था। एक सम्प्रदाय के सांसद महोदय भारतमाता की जय बोलने पर हाथापाई पर उतर आए। कन्हैयालाल जैसे कितनों की गरदन उतार दी गयी। मजहब के अलावा जातीय विभाजन गहरा हो रहा है। और दूसरा मजहब, खालिस्तानी व पूर्वोत्तर में जनजातीय एजेंडे के पीछे है। विदेशी धन लेकर दुष्प्रचारक इन आक्रमणों पर परदा डालने का काम करते हैं।

शांति का काल राष्ट्र के लिए स्थिरता विकास, शक्ति अर्जन व भविष्य की तैयारियों का काल होता है। शांतिकाल के दायित्वों का

विस्मरण करने के परिणाम हमने देखे हैं। मगध से एक साम्राज्य उठता है और भारतवर्ष की महाभारतकालीन गांधार मद्र कम्बोज की सीमाओं तक पहुंच जाता है। कौटिल्य जैसा महान दूरदर्शी विद्वान व वैसा ही महान सक्षम शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। जब मौर्य, गुप्त, कनिष्क, ललितादित्य के साम्राज्यों ने यहां तक कि अंग्रेजों ने भी पश्चिमोत्तर में हमारी इन सीमाओं की रक्षा की है तो स्पष्ट है कि यही भारतवर्ष की स्वाभाविक सीमा है। देश के बंटवारे की ये नकली विभाजक रेखाएं हमारे भाग्य की रेखायें नहीं हैं। कल जब हम समर्थ होंगे तो इतिहास की लहरों के सामने रेत की लकीरों की तरह ये मिट जाएंगी।

हमारी पूर्वी सीमाएं कभी भी हमारी समस्या नहीं रहीं। समस्या तो उत्तरी सीमाएं भी न होती। लेकिन हमारे अयोग्य शासक इसके मूल में थे। पाकिस्तान बनाकर ब्रिटिश सरकार ने पश्चिमी दिशा में हो सकने वाले भारत के शक्ति विस्तार को जानबूझकर निष्प्रभावी कर दिया। गत इतिहास में जहां सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पराजय हुई थी, आज वहां पाकिस्तान बैठा है। यह विजय न होती तो मौर्य साम्राज्य स्थिर न होता। शेष विश्व से व्यापार सम्बंध न होते। समृद्धि व शक्ति का मार्ग बाधित रहता। उसी तरह आज पाकिस्तान एक शत्रु ही नहीं, बल्कि एक बाधा है जो हमारी राह रोके खड़ा है। हमारी साम्प्रदायिक समस्या देश की आंतरिक स्थितियों को अब इस तरह प्रभावित

करने लगी है कि वह घोर साम्प्रदायिकता के साथ साथ क्षेत्रीय अलगाव का भी संबल बन रही है। यह साम्प्रदायिकता बिहार व उत्तर प्रदेश में जातीयता का अवलम्ब बन कर संकट का कारण बन रही है। बंगाल, केरल में यही साम्प्रदायिकता आतंकी विभाजनकारी अभियान का आश्रय बन चुकी है। सिमी पीएफआई एवं अलकायदा व आईएसआईएस की भारत में संगठित होने की सूचनाएं हैं। यह साम्प्रदायिक विभाजन भारतवर्ष के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर रहा है। शांतिकालीन प्रावधानों से युद्धकाल का नियंत्रण क्रमशः असंभव होता जा रहा है।

वर्तमान में शतरंज की बिसात पर दो मोहरे पाकिस्तान की ताकत बन रहे हैं। पहला तो इसकी टैक्टिकल आणविक क्षमता और दूसरा चीन का सामरिक साथ। चीन ने इसकी आणविक शक्ति को गुणात्मक क्षमता दे दी है। जब समय था तब हम इन आसन्न संकटों के प्रति जाग्रत नहीं थे। कश्मीर 1947 से ही पाकिस्तान का कोर इशू, अस्तित्व का सवाल रहा है। एक तिहाई कश्मीर उनके कब्जे में है शेष उनके अभियान का लक्ष्य है। वे मजहब पर बने हैं तो विकास वहां कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर पर कब्जा एवं भारत का इस्लामीकरण उनका लक्ष्य है। और हम ? हमारा भी कोई लक्ष्य है ? या हम बिना किसी रणनीतिक लक्ष्य के मात्र रक्षात्मक देश हैं। संकटों के बावजूद आक्रामक सैन्य सशक्तीकरण, हमारी नीति ही नहीं रही। हम तो आर्थिक समृद्धि व विकास की प्रतिज्ञा



लेकर चलने वाले देश हैं। उस राह पर मजबूती से चल भी रहे हैं। हमने युद्ध भी हमेशा रक्षात्मक किया है। 1947-48 के पाकिस्तानी आक्रमण के फलस्वरूप कश्मीर युद्ध में नेहरू जी ने सुरक्षा परिषद से युद्धविराम का निर्देश मंगवा कर उसे तत्काल लागू करा दिया।

1965 में पाकिस्तानी आक्रमण में हम लाहौर के करीब थे लेकिन हमने स्वयं युद्धविराम घोषित कर दिया। 1971 का युद्ध हम अपने नहीं, बांग्लादेश के हित में लड़े, अपने कश्मीर प्रकरण की चिंता ही नहीं की। ढाका में आत्मसमर्पण के बाद इंदिरा गांधी ने युद्धविराम घोषित कर दिया। देश पर हो रहे आक्रमणों के बावजूद हमारी अहिंसक नेताओं ने हमें समस्याओं के सैन्य समाधान का विकल्प ही नहीं दिया। समस्याएं जस की तस रहीं, तुष्टीकरण आंतरिक विरोधाभास बढ़ाता रहा।

विकास की दृष्टि से हम आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम शीघ्र ही जर्मनी व जापान से आगे निकल कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। विश्व की एक बड़ी आर्थिक एजेंसी ने इस आशय का आकलन प्रस्तुत भी किया है कि 2027 तक भारत इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

यहां यह सवाल आता है कि आर्थिक शक्ति की रक्षा, बाह्य व आंतरिक सामरिक शक्ति के अभाव में कैसे संभव हो सकेगी? शत्रु तो अंदर भी हैं। चीन हमारे सामने आंतरिक शत्रुओं के नियंत्रण का एक बड़ा उदाहरण है। रूस व यूक्रेन युद्ध के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है आर्थिक व सैन्यशक्ति का सहयोग एक दूसरे के लिए कितना आवश्यक है। राष्ट्रपति पुतिन यदि सामरिक दृष्टि से जागरूक न रहते तो वे यूक्रेन के रूप में अपनी सीमाओं पर एक पाकिस्तान जैसा सरदर्द बन जाने देते।

नाटो संगठन उनकी पक्की घेराबंदी करके उनकी योरोपीय भूमिका की संभावनाएं समाप्त कर देता। लेकिन किसी भी कीमत पर उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और युद्ध का चुनाव किया। आर्थिक समृद्धि के साथ यदि सामरिक शक्ति-सामर्थ्य नहीं होता है तो इसके बड़े भयानक परिणाम होते हैं। इसके एक बड़े उदाहरण हम स्वयं हैं। हमारी इस्लामिक गुलामी का दौर 10वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। और हम इस्लामिक आक्रमण से पूर्व के एक हजार वर्षों से भी बहुत पहले से विश्व के सबसे समृद्ध देश थे। विश्व व्यापार में हमारी भागीदार जो आज 2% से भी कम है, तब 27 से 32% के मध्य में रहा करती थी। विश्व के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार अंगुस मैडीसन ने अपने दो वाल्यूम के विशद अध्ययन में यह सिद्ध किया है कि प्राचीन विश्व की अर्थव्यवस्था का 55 से 57% भारत व चीन के नियंत्रण में था। पहले मिलीनियम में भारत चीन से आगे रहा। वही भारत सैन्यशक्ति के अभाव के कारण विश्व का सबसे समृद्ध देश होने के बावजूद जुनूनी मजहबी लुटेरों से पराजित होकर गुलामी के लम्बे दौर में दाखिल हो गया।

अमेरिका अपनी आर्थिक शक्ति की रक्षा अपनी सामरिक शक्ति से करता है। हमारे राजनैतिक नेतृत्व में भूराजनैतिक समझ का अभाव हमारी पराजयों का कारण रहा है। यदि हमें एक सक्षम समृद्ध अर्थव्यवस्था बनना है तो हमें स्वयं को एक प्रभावी सामरिक शक्ति भी बनना आवश्यक है। अमेरिका जापान आस्ट्रेलिया के साथ बना 'क्वाड', नाटो के समान एक क्षेत्रीय सामरिक संभावना है। शत्रुवत् पड़ोसियों से मित्रता की गुहार करते रहे तो हम सशक्त अर्थव्यवस्था की सीढ़ियां न चढ़ पाएंगे। □

(पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक)

## रोयें दहाड़ के

सावन सूखे  
भरे न भादों  
बहके बहके दिन अषाढ़ के,  
भाग्य हमारा  
रहे बांचते मौसम  
सूखे और बाढ़ के !

पारसाल-  
बूड़े उतर आए  
आसों सूखे की चपेट में  
कमर एक ने  
पहले तोड़ी  
दूजा मारे लात पेट में,

फिर भी रहे  
जोतते बोते  
सस्ता महंगा मूस काढ़ के !

मौसम थोखेबाज  
बहुत है  
कैसे इसका करें भरोसा  
खड़ी फसल की  
बर्बादी ज्यों  
खिसक गया है थाल परोसा,

औंधी कोठली  
और बख्खारी  
क्या रखें हम काट माड़ के !

समय चक्र के  
उलट फेर में  
यह कैसा अंधेर हो गया  
कल तक जो  
चेरापूँजी था  
अब वो जैसलमेर हो गया,

कांटा तक न  
चुभा हो जिसके  
वह क्या जाने दर्द दाढ़ के !

डा० रविशंकर पांडेय



# दुनिया का बढ़ता तापमान खतरे की घंटी



रंजना मिश्रा



ग्लोबल वार्मिंग का भीषण असर पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। कहीं जंगल की आग है तो कहीं भीषण बाढ़। कहीं सूखे के हालात हैं तो कहीं ग्रीष्म लहर नए रिकॉर्ड बना रही है। कहीं पूरे सीजन की बरसात एक हफ्ते में हो रही है तो कहीं दूर-दूर तक बारिश का नामोनिशान तक नहीं है। मनुष्यों ने अपनी गतिविधियों से तथा विकास के नाम पर प्रकृति से इस कदर छेड़छाड़ की है कि धरती की आबोहवा अब पूरी तरह बदल चुकी है। जहां आमतौर पर जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं ये 6 जुलाई को 17.08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जुलाई के 30 दिनों में धरती का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जुलाई का महीना अब तक के इतिहास का सबसे गर्म महीना रहा है, जो पिछले साल की जुलाई से करीब 1.20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह अब तक का धरती का सबसे अधिक औसत तापमान है। विश्व मौसम संगठन के वैज्ञानिकों के अनुसार, यह पिछले एक लाख 20 हजार साल का सबसे गर्म महीना है। यानी पिछले एक लाख 20 हजार सालों में धरती का तापमान इतना अधिक कभी नहीं रहा। इससे पहले सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 में बना था, जब दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल विश्व का औसत तापमान

पूरे वर्ष आमतौर पर 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2000 के बीच दुनिया का औसत तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा। धरती के बढ़ते तापमान को देखते हुए हमारी चिंता का बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि यह एक विस्फोटक रूप ले सकता है। चीन, जापान, कंबोडिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, भारत और पाकिस्तान में बाढ़ आई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए, कई जानें गईं और बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। एक ओर एशिया के इन हिस्सों में बाढ़ की स्थिति थी, तो दूसरी ओर पश्चिमी देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तथा भीषण लू चल रही थी। दरअसल हमारी धरती इतनी गर्म हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस पर अपनी गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि “यह मानवता के इतिहास का सबसे गर्म समय है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, और यूरोप के बड़े हिस्से इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए यह मुसीबत का समय है।” उन्होंने कहा कि “अब ग्लोबल वार्मिंग का दौर बीत चुका है, ये ग्लोबल बॉयलिंग का दौर है।

बढ़ते तापमान का सबसे बुरा असर अंटार्कटिका जैसे इलाकों पर पड़ रहा है। जहां सामान्यतया मार्च के महीने में अंटार्कटिका का तापमान माइनस 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहीं साल 2022 के 18 मार्च को यहां का तापमान माइनस 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दरअसल पृथ्वी की जलवायु में हो रहे परिवर्तन की गंभीरता का अंदाजा अंटार्कटिका महाद्वीप के टूटते ग्लेशियरों को देखकर लगाया जा सकता है। इन ग्लेशियरों के टूटने का असर अमेरिका से लेकर एशिया तक पड़ रही भयंकर गर्मी के रूप में और दक्षिणी



यूरोप के जंगलों में लगने वाली भयंकर आग के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अंटार्कटिका में दुनिया के पहाड़ों पर मौजूद सभी ग्लेशियरों की तुलना में 50 गुना ज्यादा बर्फ मौजूद है। इन ग्लेशियरों के पिघलने से पृथ्वी का तापमान करीब 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इस गर्मी को झेल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं होगी। ग्लेशियरों के पिघलने से दुनिया भर में पीने के शुद्ध पानी के खत्म होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये ग्लेशियर प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ के एक विशाल भंडार के रूप में मौजूद हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर करीब दो लाख ग्लेशियर हैं।

धरती के बढ़ते तापमान और मौसम में हो रहे बदलावों का सबसे बड़ा कारण इंसानी गतिविधियां ही हैं। आधुनिक विकास और औद्योगीकरण के चलते फैक्ट्रियों-कारखानों से निकलता धुंआ, सड़कों पर दौड़ते वाहन, ट्रेनें, समुद्री जहाजों और विमानों से निकलती जहरीली गैसें, खेतों में रासायनिक खादों का अधिक इस्तेमाल, फ्रिज, एसी और ठंडक पैदा करने वाले उपकरणों का बढ़ता उपयोग तथा डेयरी उद्योग के लिए बढ़ता पशुपालन आदि कई ऐसे कारण हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मनुष्य की गतिविधियां और धरती के मौसम में हो रहा ये बदलाव अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ के बहुत तेजी से पिघलने का

कारण बन रहा है। अंटार्कटिका से दूटते ग्लेशियर समुद्र में पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। समुद्र की गर्म और ठंडी धाराएं दुनिया भर के मौसम को बनाती-बिगाड़ती हैं। लेकिन अब इन धाराओं के पैटर्न बदल रहे हैं। अटलांटिक महासागर में मेरिडियन ओवरटर्निंग करंट यानी एएमओसी चलती है, जो साउथ अटलांटिक से गर्म पानी को नॉर्थ अटलांटिक की तरफ ले जाती है। जहां के सर्द मौसम में ये धारा ठंडी हो जाती है और ये ठंडी धाराएं एक बार फिर दक्षिण की ओर जाती हैं। दुनिया भर के मौसम को तय करने में एएमओसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्लेशियर पहले की तुलना में इतनी अधिक तेजी से पिघल रहे हैं कि इस साल अंटार्कटिका की बर्फ में अर्जेंटीना जैसे बड़े देश के बराबर क्षेत्रफल में कमी आई है। यह बर्फ पिघल कर समुद्र के पानी में मिल गई। इससे दुनिया का मौसम तय करने वाले समुद्र का मिजाज बिगड़ गया और इसका असर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में भयंकर बारिश, बाढ़, जंगल में आग और झुलसाती गर्मी के रूप में दिखाई दे रहा है। जानकारों का मानना है कि मौसम में हो रहे बदलाव हर साल नए-नए रूप में सामने आएंगे। जैसे इस साल भयंकर गर्मी की वजह से पहली बार कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटनाएं देखी गईं। ईरान में तापमान 150 डिग्री फारेनहाइट यानी 65.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। धरती के सबसे गर्म स्थानों में से एक कैलिफोर्निया की डेथ वैली में 16 जुलाई को तापमान 53.33 डिग्री सेल्सियस मापा गया। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले 5 साल में धरती का तापमान नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा।

अमेरिका से लेकर यूरोप तक, चीन से लेकर भारत तक पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा है। इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण पूरी दुनिया शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान झेल रही है। कनाडा के जंगलों में लगी आग ने करीब ढाई करोड़ एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर दिया। अमेरिका को हर साल भयंकर गर्मी से करीब 100 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें बाढ़, तूफानों और जंगलों में लगने वाली आग से होने वाले नुकसान को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा कई गुना हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर के लाखों लोग सूखा, अकाल, भुखमरी, पीने के पानी का

## समुद्र बदलता पानी है भयावह

एक शोध में पता चला है कि पिछले दो दशकों के दौरान समुद्र का 56 प्रतिशत हिस्सा नीले से हरा हो गया है। वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी में हो रहे इस परिवर्तन को बेहद भयावह बताया है। दरअसल जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की सतह पर फाइटोप्लांकटन जीवों की संख्या बहुत बढ़ गई है। ये जीव छोटे पौधों की तरह दिखते हैं और इनमें पौधों की तरह ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के हरे रंग की वजह से पानी की सतह भी हरी दिखाई देती है। फाइटोप्लांकटन के बनने से समुद्र में दूसरे समुद्री जीव-जंतुओं के लिए जगह कम हो रही है और पानी में आक्सीजन की कमी होने के कारण उनका जीवन संकट में पड़ गया है।

दरअसल इंसानों तथा दुनिया के बढ़ते तापमान के कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। समुद्र के पानी का रंग बदलना भी पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का संकेत है। समुद्री जीवों तथा इंसानों की एक बड़ी आबादी समुद्री जीवन पर निर्भर है। समुद्र में ऐसे मृत क्षेत्र (डेड जोन) बनने से समुद्री जीवन समाप्त हो जाएगा और इससे इंसानों के लिए भी रोजी-रोटी का खतरा पैदा हो जाएगा।

संकट, बाढ़ आदि विपदाओं का सामना करते हैं। इसका सबसे अधिक असर गरीब और विकासशील देशों पर पड़ता है, जबकि ये देश जलवायु परिवर्तन के लिए उतने जिम्मेदार नहीं हैं, जितने कि विकसित देश हैं।

दुनिया का 20 प्रतिशत उत्सर्जन परिवहन



द्वारा होता है, जिसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है सड़क यातायात। इसलिए उत्सर्जन को कम करने के लिए पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाय ई-वाहन तथा सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा। जहां तक संभव हो हमें साइकिल का उपयोग करना चाहिए और थोड़ी दूरी तय करने के लिए पैदल चलने की आदत डालनी चाहिए। इसी प्रकार विमान से सफर करने की बजाय अगर रेल से सफर किया जाए, तो उतनी ही दूरी के लिए विमान की तुलना में ट्रेन का सफर 90 फीसदी कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। मीट और डेयरी उत्पाद से लगभग 15 फीसदी वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन

होता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में शाकाहारी होना या वीगन आहार लेना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा सरकार पर उत्सर्जन कटौती के लक्ष्यों को मजबूत करने के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीवाश्म ईंधनों के जलाए जाने से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है। इसलिए ऊर्जा के स्वच्छ और अक्षय स्रोत जैसे- सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि से हरित ऊर्जा प्राप्त करने का प्रावधान करना चाहिए। कार्बन उत्सर्जन करने वाला सबसे जिम्मेदार जीवाश्म ईंधन कोयला है और कई देशों में अधिकांश बिजली कोयले से ही पैदा की जाती है। किंतु अब धीरे-धीरे सौर ऊर्जा का चलन बढ़ रहा है और सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली पैदा की जा रही है। सौर ऊर्जा एक अक्षय ऊर्जा है, जिस पर निर्भरता जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मददगार साबित होगी। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए भोजन की बर्बादी रोकनी होगी, क्योंकि कचरे में फेंका गया भोजन मीथेन पैदा करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है।

अमेरिका में हर साल ख़ाद्य कचरे से करीब 17 करोड़ मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो कोयले से चलने वाले 42 ऊर्जा संयंत्रों के सालाना उत्सर्जनों के बराबर है। वैश्विक तापमान को कम करने और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में वृक्षारोपण का कार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि पेड़ कार्बन सिंक का काम करते हैं, जिससे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होती है। □





# देश विरोधी नापाक फंडिंग का नेटवर्क

बताया गया है कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ हासिल हुए हैं और यह पैसा कुछ पत्रकारों में बांट दिया गया है।

एक रिपोर्ट पेश करते हुए न्यूयार्क टाइम्स

करने और देश के खिलाफ 'धुआं-रहित युद्ध' छेड़ने के अभियानों में संलिप्त है, तो बेशक वह 'देशद्रोही' है। उसके खिलाफ यूएपीए, राजद्रोह के कानून और अन्य धाराओं में केस चलाया जाना चाहिए। यदि भारत के खिलाफ किसी देश का एजेंडा है और वह दुष्प्रचार की साजिशें रच रहा है, तो उसके स्वदेशी दलालों, गद्दारों के खिलाफ भी आपराधिक मामले चलने चाहिए। अमरीका के प्रख्यात अखबार 'न्यूयार्क टाइम्स' ने कुछ साक्ष्यों और संदर्भों के साथ चीन के मंसूबों को बेनकाब किया है।



रोहित माहेश्वरी  
9450900065



'न्यूज क्लिक' एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर बीजेपी ने चीन का साथ देकर भारत में माहौल खराब करने का आरोप लगाया। यह पोर्टल ईडी के छापों के चलते पहले भी चर्चा में रह चुका है। दो साल पहले ईडी ने बताया था कि न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल हुई है। साथ ही बीजेपी की ओर से यह भी आरोप लगा कि 2005 से 2014 के बीच जब भी कोई संकट आया कांग्रेस को भी चीन से पैसा मिला है। अब द न्यूयार्क टाइम्स रिपोर्ट में

ने लिखा कि गैर-लाभकारी मीडिया संस्थाओं के बारे में छुपी एवं अस्पष्ट बात यह है कि नेविल राय सिंघम चीनी सरकार के साथ काम करते हैं और पूरी दुनिया में अपने प्रोपेगेंडा को प्रसारित करने के लिए मीडिया संस्थान को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। नेविल राय सिंघम के नेटवर्क ने दिल्ली स्थित आनलाइन न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक को आर्थिक सहायता दी थी। यह वेबसाइट चीनी सरकार के विचारों को बढ़ावा देती है। नेविल राय सिंघम अमेरिका का नागरिक है लेकिन वो क्यूबा-श्रीलंका मूल का है।

न्यूयार्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा, "शी जिंपिंग के शासन काल में मीडिया के विस्तार एवं विदेशी प्रभावशाली मीडिया पर ध्यान दिया गया। इसका मकसद स्वतंत्र कंटेंट के नाम पर चीनी प्रोपेगेंडा को छुपाना है। इसका प्रभाव पड़ता देखा गया है। कट्टर वामपंथी समूह चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं और इसके बदले में चीनी संस्था आर्थिक सहायता करती है।"

यदि कोई भारत-विरोधी, देश को खंडित

यह अखबार भारत का हमदर्द भी नहीं है। हमारे देश के खिलाफ बहुत कुछ प्रकाशित होता रहा है, लेकिन अब चीन को नंगा करने वाले आलेख और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के निष्कर्षों में बहुत कुछ समानताएं हैं, लिहाजा चीन का एजेंडा हमारा चिंतित सरोकार है। हालांकि ईडी ने कथित मीडिया वेबसाइट 'न्यूज क्लिक' पर छापे की कार्रवाई फरवरी, 2021 में की थी। छापे लगातार 5 दिन तक चले थे और कंपनी के 10 ठिकानों पर छापे मारे गए थे, जिनमें 38 करोड़ रुपये से अधिक की फंडिंग का खुलासा हुआ था। कुछ पैसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए आया और अधिकांश राशि हवाला के जरिए भेजी गई। वेबसाइट के संस्थापक एवं संपादक प्रवीर पुरकायस्थ से भी करीब 11 घंटे तक पूछताछ की गई थी। तब वामदलों और कांग्रेस सरीखे दलों ने मीडिया कंपनी का बचाव किया था और ईडी की कार्रवाई को स्वतंत्र मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दिया था।

अब 'न्यूयार्क टाइम्स' के आलेख से खुलासा हुआ है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी



अमरीकी उद्योगपति नेविल राय सिंधम के जरिए भारत की मीडिया कंपनी को ही नहीं, बल्कि माओवादी गौतम नवलखा, सीपीएम के आईटी प्रकोष्ठ के बप्पादित्य सिन्हा, तीस्ता सीतलवाड़, उनके पति एवं बच्चों तथा ऐसे कई स्वतंत्र पत्रकारनुमा चेहरों को भी फंडिंग कराती रही है। कुछ पत्रकारों की जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां भी की गई हैं। नवलखा भीमा कोरेगांव दंगा केस में अब भी जेल में है। अखबार में छपे आलेख से खुलासा हुआ है कि चीन अफ्रीकी राजनीतिक दलों, गैर लाभकारी संगठनों और तीसरी दुनिया के देशों के कथित पत्रकारों की भी फंडिंग करता रहा है।

अमरीकी नेविल राय मूलतः श्रीलंका का है और आजकल चीन के शंघाई शहर में रहता है। उसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रचार मशीनरी का एक अंतरंग हिस्सा माना जाता है। वह खुद को 'कम्युनिस्ट' कहलाना पसंद करता है। चीन की फंडिंग कुछ अमरीकी कंपनियों और ब्राजील की एक कंपनी के जरिए की गई है, जिसे 'न्यूज क्लिक' में विदेशी निवेश दिखाया गया है। इस नापाक नेटवर्क का सरगना नेविल राय ही है। 'न्यूयार्क टाइम्स' में ये तमाम खुलासे छपने के बाद भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन में यह मुद्दा उठाया और सरकार से जांच का आग्रह किया। सूचना-प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की कथित मिलीभगत और राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चीनी चंदे सरीखे पुराने मुद्दे एक बार फिर खोल दिए।

दरअसल चीन अपने दुष्प्रचार के अभियान को चलाए रखने और चीनी एजेंडे की व्यापक कवरेज के लिए यह अवैध फंडिंग करता रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि 'न्यूज क्लिक' चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हथियार है। चीन बुनियादी तौर पर हमारा दुश्मन देश है, बेशक उसके साथ लाखों करोड़ रुपए का कारोबार करना हमारी मजबूरी है। यदि देश का मीडिया इस तरह 'बिकाऊ' होने लगा और चीन के गुणगान करने लगा, तो जनता का भरोसा भी उठेगा और देश भी कमजोर होगा।

सवाल अब यह है कि आखिर कांग्रेस सवालियों के घेरे में क्यों हैं। बीजेपी की ओर से क्यों इस मामले में कांग्रेस को घसीटा जा रहा ? दरअसल, बीजेपी का अब आरोप है कि जब दो साल पहले उन्होंने न्यूज क्लिक के खिलाफ मोर्चा खोला था तो कांग्रेस उस समय पोर्टल का बचाव कर रही थी। अनुराग ने कहा कि, घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते हैं। भारत को कमजोर कैसे करना है, कैसे भारत विरोधी एजेंडे को हवा, खाद और पानी दिया जाए ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं।

अनुराग ठाकुर ने आगे कहा, “भारत लंबे समय से

दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक वैश्विक जाल है। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। अब राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान साफ नजर आने लगा है।” कांग्रेस के लिए नेविल और न्यूजक्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है। यह वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2008 में सीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और कथित तौर पर चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) के लिए दान स्वीकार किया था ?

इस नापाक फंडिंग का देशव्यापी विरोध करने के बजाय हम इस बहस में उलझे रहेंगे कि चीन ने हमारी कितनी जमीन कब्जा रखी है, लद्दाख और गलवान में क्या हुआ, चीन ने हमारे सैनिकों को पीट दिया, तो यही दुष्प्रचार चीन चाहता है। चीन इसी तरह भारत को विभाजित करना चाहता है। भारत को वैश्विक स्तर पर बदनाम करना चाहता है। लिहाजा 'काली भेड़ों' को दंडित करें और चीन के षड्यंत्र का माकूल जवाब दें। तभी चीन का एजेंडा नाकाम हो सकता है। सीमा पर भी चीन बार-बार हरकत करता रहता है। उसे करारा जवाब दिया जाना चाहिए।

सुरक्षा और अर्थ क्षेत्र की जांच एजेंसियों को ऐसे नापाक गठजोड़ और पत्रकारिता की आड़ में देशविरोध का एजेण्डा चलाने वाले चेहरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इस मामले पर राजनीति की बजाय उचित और ठोस कार्यवाही होनी चाहिए। □







लक्ष्य पीछे छूटा, रिकार्ड पौधरोपण

**रोपे पौधे**

**30.21 करोड़**

### पौधरोपण लोकपर्व : योगी

मुख्यमंत्री ने पौधरोपण को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में पौधरोपण को लोक पर्व बताया।

उन्होंने कहा कि एक दिन में 30 करोड़ से अधिक पौधरोपण का कीर्तिमान बना है। सरकार ने प्रदेश का हरित आवरण नौ फीसदी से बढ़कर 15 फीसदी का लक्ष्य रखा है। ऐसे पौधरोपण से प्रदेश की जैव विविधता मजबूत हो रही है। प्रदेश में बाघ, हाथी, सारस और गिद्धों में इजाफा हुआ है। इस पौधरोपण अभियान से लगाए गए पौधे रोज 7903 करोड़ लीटर से अधिक ऑक्सीजन पैदा करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की अगुवाई में चले 'वृहद वृक्षा रोपण अभियान' ने इतिहास रच दिया। लक्ष्य था एक दिन में 30 करोड़ पौधों के रोपण की। लेकिन सुबह से शाम तक चले

आयुष सिंह



### पौधरोपण में टॉप-5 में लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट व मिर्जापुर मंडल

पौधरोपण अभियान में इतिहास इस वजह से बन पाया कि क्योंकि लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट व मिर्जापुर मंडल ने बढ़ चढ़कर इस महा अभियान में हिस्सेदारी निभाई। जबकि लखनऊ में सर्वाधिक चार करोड़ पौधे रोपे गए। जबकि कानपुर में 3.13 करोड़, चित्रकूट में 2.76 करोड़, झांसी में 2.58 करोड़ और मिर्जापुर मंडल में 2.27 करोड़ पौधे रोपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन वन विभाग के अनुसार इससे कहीं अधिक पौधे रोपे गए। बावजूद इसके जहां कई जगहों पर पौधरोपण को इतिहास बना तो वहीं लाख जतन के बावजूद 14 सरकारी विभागों की इस अभियान में हिस्सेदारी फिसड्डी साबित हुई।

पीपल, पाकड़, गूलर, नीज, शहजन, जामुन, देशी आम, बांस, शहतूत, सागौर सहित विभिन्न इमारती व फलदार प्रजातियों का रोपण कर वन ग्राम्य की स्थापना भी की गई है। इसी के साथ नंदनवन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हर बहेड़ा, महुआ, चिरौंजी, इमली आदि पौधों का रोपण हुआ है। जबकि नीम, अर्जुन, बेल आंवला, अशोक, बबूल, कैथा आदि का रोपण कर आयुष्मान की स्थापना की गई है।

इस महा अभियान के अंतर्गत प्रदेश में कुल

30 करोड़ 21 लाख 51 हजार पौधे

रोप दिए गए। वैसे प्रदेश में

इस साल 35 करोड़ पौधे

लगाने का लक्ष्य रखा

गया है। 30

करोड़ पौधे 22

जुलाई को रोपे

गए जबकि

बाकी 5

करोड़ के

आसपास

15 अगस्त

को पौधे रोपे

जाएंगे। वन

विभाग के

अनुसार पिछले

साल एक दिन में

25 करोड़ पौधे लगाए

गए थे। वन विभाग का यह

भी दावा है कि प्रदेश में विगत छह

सालों में 136.98 करोड़ पौधे लगाए

गए। इसमें वन विभाग की ओर से 49.88

करोड़, अन्य विभागों की ओर से 82.10 करोड़

पौधरोपण किया गया है। इस महा अभियान में

कुल 85 सरकारी विभागों ने सभी 75 जिलों

में पौधरोपण अभियान को अंजाम दिया।

मुख्यमंत्री ने खुद बिजनौर के विदुर वन

और मुजफ्फरनगर के शुक्रतीर्थ में बन रही

पंचवटी में पीपल का पौधा लगाकर जहां इस



महा

अभिय

ान की शुरुआत

की साथ ही मुख्यमंत्री ने वन विभाग के नए

लोगो और 'वन आधारित व्यंजन' पुस्तिका का

विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री के साथ ही दोनों

ही जगहों पर जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह

और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य

मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने भी इस महा अभियान

में शिरकत की। तो वहीं राज्यपाल आनंदी बेन

पटेल ने मथुरा के संस्कृत विश्वविद्यालय छाता में हरी शंकरी का पौधा रोपा।

प्रदेश सरकार ने इस महाअभियान को इतिहास बनाने की दिशा में पूरा जोर लगा दिया था। क्योंकि इस

महा अभियान में सभी मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई थी। सभी मंत्रियों को जहां दो-दो जिलों में पौधरोपण का जिम्मा सौंपा गया था तो वहीं मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भी जिलों में पौधरोपण की जिम्मेदारी दी गई थी। वन विभाग ने पौधों की गणना के लिए विशेष कंट्रोल रूम बना रखा था। सभी पौधरोपण स्थलों से कंट्रोल रूम में अपडेट देने के साथ ही वन विभाग की वेबसाइट पर सीधे फोटो और वीडियो अपलोड करने की व्यवस्था थी।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य ने कौशाम्बी और प्रयागराज में पौधरोपण किया तो वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने लखनऊ और बाराबंकी में बालमखरी, घृतकुमारी और शरीफे के पौधे रोपे।

इस महा अभियान में लखनऊ में हरियाली के लिए 27 लाख पौधे रोपे गए। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने पौधरोपण के अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं, यह सब पर्यावरण की दृष्टि से बहुत लाभाकारी हैं। लेकिन इसी के साथ कहा कि सिर्फ पौधे लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनका संरक्षण भी बेहद जरूरी है। पौधे लगाना ही प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि उसे बचाने पर भी खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सीजी सिटी स्थित नंदनवन में पौधरोपण किया। यहां 40 एकड़ में नंदनवन विकसित किया जा रहा है।





# वृहद वृक्षारोपण अभियान 2023



स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित वृहद वृक्षारोपण अभियान के द्वितीय

विशेष कार्याधिकारी, श्री महाराम सिंह विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती साक्षी शर्मा विशेष कार्याधिकारी, श्रीमती रेश्मा सहाय विशेष

चरण में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकरण के अन्य अधिकारीगण श्री कपिल सिंह अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री शैलेन्द्र भाटिया विभागाध्यक्ष कार्याधिकारी, शैलेन्द्र सिंह

कार्याधिकारी, विशम्भर बाबू महा प्रबंधक वित्त, अशोक कुमार उप महाप्रबंधक वित्त, ए. के. सिंह महाप्रबंधक परियोजना, सीपी सिंह वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भाटी उप महाप्रबंधक परियोजना, नंदकिशोर स्टॉफ आफीसर एवं आनंद मोहन सिंह उपनिदेशक उद्यान तथा प्राधिकरण के समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे।

यमुना प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्य एक लाख पौधे दिया गया है। जिसके सापेक्ष नीम, पीपल, अशोक, जामुन, मौलश्री इत्यादि कुल 1,01,658 पौधों को लगाये जाने का कार्यक्रम दिया गया है। इसी क्रम में लक्ष्य के सापेक्ष मानसून सत्र के प्रथम चरण में लगभग 85 हजार पौधे विगत 22 जुलाई को लगाए गए थे। द्वितीय चरण में 14 अगस्त को 16 हजार 658 पौधे लगाए गए हैं। वृक्षारोपण कार्य हेतु यमुना प्राधिकरण की ओर से से नोडल अधिकारी श्रीमती डा. आरती सिंह, सहायक निदेश उद्यान को नामित किया गया है।

विभिन्न सड़कों, ग्रीन बेल्टों एवं पार्कों में नीम, जामुन, पीपल, पिल्लखन, गुहमोहर, चकरेसिया, बरगद, चंपा, अशोक आदि पौधे लगाए गए हैं।

## डा. राजेश्वर सिंह को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड



दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले सरोजनीनगर के विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड -2023 से नवाजा गया।

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में

सहित 12 विभूतियों को यह अवार्ड दिया गया। तमना की अध्यक्ष डॉ. शायमा चोना को दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण सम्मान मिल चुके हैं। सरोजनीनगर विधायक ने 1500 से अधिक दिव्यांगजनों को

चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई चंद्रचूड़ ने उनको यह सम्मान दिया।

शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था 'तमना' ने फिलांथ्रोपिस्ट श्रेणी में सरोजनीनगर विधायक को चुना। डॉ. राजेश्वर सिंह

अब तक सहयोग उपलब्ध कराया। इनमें 350 से अधिक ट्राईसाइकिल, 102 व्हीलचेयर, 360 से अधिक दिव्यांगों को क्रूज, वॉकिंग स्टिक्स, ट्राईपॉड्स व हियरिंग एड्स दिया जाना शामिल है।

इसके अलावा उनकी टीमों ने गांव-गांव जाकर दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी जुटाई। जिससे उनको सरकारी योजनाओं के लाभ के अलावा इलाज आदि की सुविधा दिलाई जा सके।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराना, उनकी खुशियों का कारक बनना, उन्हें भावनात्मक सहारा देना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया।

# एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता : योगी



**मु**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है। इसे आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर अनेक कदम उठाए हैं। 'उड़ान योजना' के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज यात्रा कर सके। उत्तर प्रदेश ने इस स्वप्न को साकार किया है। प्रदेश में वायु सेवा का तेजी के साथ विस्तार हुआ है।

चौधरी चरण सिंह अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इण्डिगो एयरलाइन्स द्वारा लखनऊ-वाराणसी रूट पर नयी उड़ान सेवा आरम्भ किये जाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्हें इण्डिगो एयरलाइन्स की ओर से बोर्डिंग पास दिया गया। मुख्यमंत्री ने हरी झण्डी दिखाकर लखनऊ से वाराणसी उड़ान का शुभारम्भ किया तथा प्रथम उड़ान के एक यात्री को बोर्डिंग पास दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वाराणसी और देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। जनपद वाराणसी ने विगत 09 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। काशी ने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस दृष्टि से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वाराणसी को हवाई सेवा से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वर्ष 2016-17 में वाराणसी से एक वर्ष में 19 लाख यात्रियों ने यात्रा की थी। गत वर्ष

2022-23 में यह संख्या बढ़कर 25 लाख से अधिक हो चुकी है। यह वाराणसी के पोर्टेशियल को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 06 वर्षों में वायु सेवा का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ में दो पूरी तरह क्रियाशील हवाई अड्डे थे। गोरखपुर और आगरा के हवाई अड्डे आंशिक रूप से क्रियाशील थे। प्रयागराज कुम्भ के दौरान वहां एयरपोर्ट की सुविधा प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 09 पूर्ण क्रियाशील एयरपोर्ट हैं तथा 12 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है, इनमें दो नए इन्टरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शामिल है।

अयोध्या का अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट इस वर्ष नवम्बर-दिसम्बर तक क्रियाशील हो जाएगा। गौतमबुद्धनगर के जेवर में राज्य सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। इसका पहला रनवे इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ हो जाएगा। यह कार्गो की ढुलाई में वृद्धि कर उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के हब के रूप में स्थापित करेगा। आजमगढ़, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ तथा सहारनपुर में भी एयरपोर्ट बन रहे हैं। इन सभी को शीघ्र ही वायु सेवा से जोड़ा जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी आफ इण्डिया ने प्रदेश सरकार के साथ 05 एयरपोर्ट के संचालन के लिए एम0ओ0यू0 किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में बहुत सारी सम्भावनाएं हैं। आने वाले

समय में लगभग 2000 एयरक्राफ्ट भारतीय बाजार में आने वाले हैं, जो वायु सेवा को बेहतर करने, लोगों की उड़ान और उनकी महत्वाकांक्षाओं को एक नई दिशा देने में योगदान करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा के लिए सबको तैयार होना होगा। आज का समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का है, जो इसमें क्वालिटी देगा तथा समयबद्धता के साथ आगे बढ़ेगा वहीं इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाएगा। इस प्रतिस्पर्धा का लाभ इण्डिगो ले रही है और अपनी सेवाएं आम नागरिकों को उपलब्ध करा रही है।

केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल (डॉ०) वी०के० सिंह (सेवानिवृत्त) ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में उड़ान योजना के अन्तर्गत अनेक कार्य किये जा रहे हैं। आज इण्डिगो द्वारा लखनऊ से वाराणसी के मध्य शुरू की जा रही हवाई सेवा से दोनों महत्वपूर्ण जगहों पर लोगों के लिए यात्रा सुगम होगी। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बाबा विश्वनाथ की नगरी आने-जाने में सहूलियत होगी।

इस अवसर पर इण्डिगो के सी०ई०ओ० श्री पीटर एल्बर्स ने कहा कि आज वाराणसी को लखनऊ से हवाई मार्ग से जोड़ने पर उन्हें गर्व है। यह राज्य में घरेलू कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इण्डिगो एयरलाइन्स हवाई यात्रा के माध्यम से देश के अनेक राज्यों को जोड़ने के लिए कटिबद्ध है।



# जड़ से जोड़ने की मुहिम

## विश्व नागरिक के रूप में विश्व का नेतृत्व करें छात्र : रामदेव

टी.बी. सिंह  
वीरेन्द्र सिंह



**मा** नवीय मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन हो रहा है। हर क्षेत्र में गिरावट महसूस हो रही है। वजह साफ है, हमारी वर्तमान शिक्षा संस्कार नहीं दे पा रही है। दरअसल, शिक्षा मानव-निर्मात्री, चरित्र-निर्मात्री होनी चाहिए। छात्र के अंदर अनंत शक्तियां होती हैं। उनका प्रस्फुटन शिक्षा के माध्यम से होना चाहिए।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन क्यों हुआ ?

काफी समय से महसूस किया जा रहा था कि मौजूदा शिक्षा पद्धति छात्रों को हमारे अतीत के गौरव से विरत करती है। प्रामाणिक मानव नहीं बना पाती है। जबकि मानव को संस्कृति, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति निष्ठावान संस्कारों की आवश्यकता होती है। आदर्श नागरिक बनने के लिए मनुष्य का प्रबोधन जरूरी है। आज की शिक्षा तो आजीविका संसाधन और धन-संपन्नता अर्जित करने का उपकरण मात्र बन गई है। प्रसिद्ध विचारक जे.कृष्णमूर्ति के शब्दों में, 'शिक्षा का मतलब कुछ परीक्षाएँ पास कर लेना नहीं होता है, बल्कि सभी समस्याओं पर विचार करने के योग्य बनाना होता है। शिक्षा का तात्पर्य यही है कि आप स्वतंत्रतापूर्वक बेरोकटोक विकसित हो सकें। 'शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ना जरूरी है। संस्कृति उच्चतर मूल्यों के संवर्धन का ही नाम है।' भारत के संविधान में इसे मूल कर्तव्यों के अंतर्गत 'सामासिक संस्कृति' कहा गया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि संस्कृति का आधार संस्कृत भाषा और साहित्य है। यही

भिन्न-भिन्न जनों को एक सूत्र में बांधने का आधार भी है।

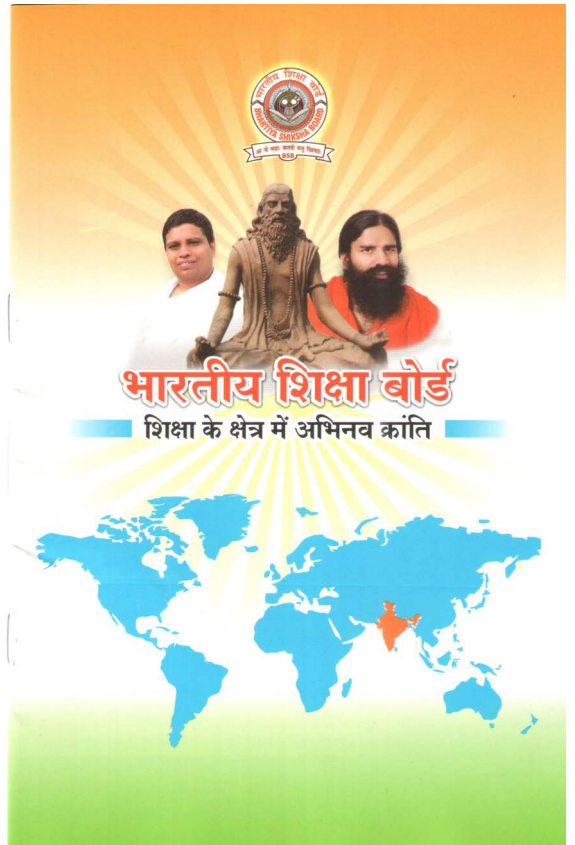
1835 में लार्ड मैकाले ने शिक्षा की नींव इसलिए रखी थी, ताकि भारत के लोग सिर्फ नौकरी करने वाले बने, उनके अंदर आत्मबोध और राष्ट्रबोध के प्रति जागरूकता ना हो सके, जिससे भारतीय लोग उनके सदा गुलाम बने रहें। बच्चे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बने रहे और उनके अंदर संस्कार नाम की कोई चीज न रहे।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन:

आजादी के 75 साल बाद आजादी के महोत्सव मना रहे देशवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। इसका आधार स्वामी रामदेव के द्वारा बनाया गया था।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष डा. एनपी सिंह ने बताया कि इससे देश के लाखों स्कूलों को जोड़ा जाएगा और इसमें तैयार किए गए सिलेबस का पढ़ाई बच्चे करेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़े हुए बच्चे ज्ञानवान होने के साथ ही संस्कारित भी बनेंगे। उनके अंदर देश एवं अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता होगी। इसके सिलेबस में वर्तमान में जो शिक्षा है उसमें सुधार करके उसे भी रखा जाएगा। साथ ही अलग से धर्म एवं संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया जाएगा।

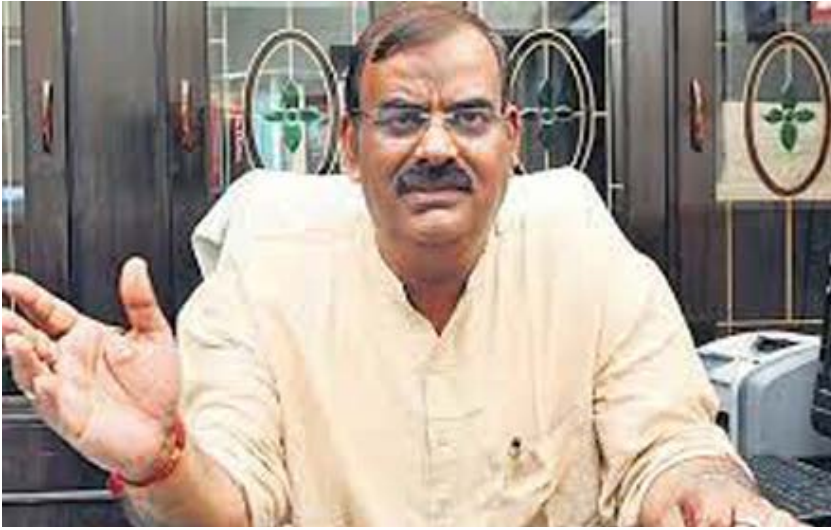
अभी तक कान्वेंट स्कूल या सरकारी स्कूलों में सिर्फ अक्षर का ज्ञान दिया जाता था जिसमें बच्चों के अंदर भारत की संस्कृति, सभ्यता और किसी भी तरह का संस्कार नहीं हो पाते थे। शिक्षा के भारतीयकरण का काम स्वामी रामदेव ने पतंजलि से करने का शुरुआत किया



है। स्वामी रामदेव का कहना है कि 1835 में लार्ड मैकाले का पाप धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के जरिए भारतीय लोगों के शिक्षा में वर्तमान शिक्षा के साथ ही अध्यात्म शिक्षा भी पढ़ाई जाएगी।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड क्या है ?

इस बोर्ड के जरिए भारत के बच्चों का मानस भारत और भारतीयता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जिस तरह से CBSE Board होता है, ICSC Board होता है, उसी तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड को पहली बार मान्यता 4 अगस्त 2022 को भारत सरकार के तरफ से दी गई है। सन 1835 में मैकाले के द्वारा विदेशी शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें सिर्फ अक्षर का



ज्ञान बच्चों को दिया जा रहा था लेकिन अब धीरे-धीरे ये शिक्षा पद्धति समाप्त हो जाएगी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के जरिए स्वदेशी शिक्षा लागू होगी, जिसमें अध्यात्म की भी शिक्षा रहेगी।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड के फायदे क्या हैं ?

भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के अंदर आत्मबोध होगा, भारतबोध होगा और जो व्यक्तित्व एवं नेतृत्व उनके अंदर पैदा होगा। पहले मैकाले के द्वारा बनाया गए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वे अपनी विरासत के ज्ञान से वंचित रह जाते थे।

स्वामी रामदेव एवं नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि शिक्षा का स्वदेशीकरण हो और भारतीयकरण हो। अध्यात्म पर आधारित पाठ पढ़ाये जाने का सपना पूरा होते हुए दिख रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के सबसे बड़ा फायदे यह है कि इसमें सिर्फ अक्षर का ही ज्ञान नहीं दिया जाएगा बल्कि भारत के सभ्यता संस्कृति एवं अध्यात्म से जुड़ी पढ़ाई भी कराई जाएगी एवं इतिहास में बहुत कुछ गलत चीजें बताई जा रही थी, जिसे अब सुधारा जाएगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़कर निकले हुए बच्चे अपने धर्म एवं देश के प्रति जागरूक रहेंगे और ऐसे कमाने के साथ ही अपने घर परिवार एवं देश के लोगों का भी पूरा ख्याल रखेंगे क्योंकि उनके अंदर भारत की संस्कृति भरी जाएगी।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों ?

स्वामी रामदेव जी के अनुसार लार्ड मैकाले ने भारत को हमेशा के लिए सांस्कृतिक उपनिवेश बनाने का जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र को भारत बोध के साथ उसका समाधान करने के लिए उन्होंने पिछले एक दशक से ये

संकल्प लिया हुआ था। भारतीय शिक्षा बोर्ड एक ऐसा समर्थ बोर्ड होना चाहिए, जिसमें भारतीय बच्चों को भारतीय संस्कृति के समस्त प्रवाह और निरंतरता के साथ आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक और नूतन दोनों के समन्वय के साथ शिक्षा दी जाए।

भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे केवल पैसे कमाने की मशीन ही नहीं बनेंगे बल्कि उनके मन में अपने देश एवं संस्कृति के प्रति गौरव का बोध रहेगा। इस संकल्पना को वर्तमान में नरेंद्र मोदी के सरकार ने भारत के 75 वे अमृत महोत्सव के दौरान मैकाले के उस विषाक्त शिक्षा पद्धति के समाधान के रूप में वैधानिक स्वरूप दिया है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार ने अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से अमलीजामा पहनाया। इस प्रक्रिया में समस्त दृष्टि से समस्त आयामों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद पतंजलि योगपीठ को वैधानिक रूप से स्पान्सरिंग बॉडी चयनित किया गया।

भारतीय शिक्षा बोर्ड में कुल 18 सदस्य हैं, जिसमें 7 सदस्य भारत सरकार के हैं और उसमें पांच कुलपति स्तर के लोग भारत सरकार से नामित हैं। निदेशक NCERT और चेयरमैन सीबीएसई (CBSE) भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य हैं। बाकी के जो बोर्ड के सदस्य हैं उसके लिए स्वामी रामदेव जी को अधिकार था कि वो उन सदस्यों को नामित कर सकते हैं। स्वामी जी ने जिन सदस्यों को नामित किया है वह वैदिक संस्कृति भारत के ज्ञान परंपरा में या तो उच्च दर्जे के हैं या आधुनिक शिक्षाविदों के जो भारत में प्रथम सूची

है उसमें सम्मिलित हैं।

### क्या ये बोर्ड वैधानिक रूप से पूरे भारत में संचालन के लिए सक्षम है ?

3 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने स्वामी रामदेव के इच्छा को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा बोर्ड को जो वैधानिक रूप से गठन किया था। उसको भारत के समस्त केंद्रीय बोर्ड और राज्य बोर्ड के समकक्ष समस्त दृष्टि से घोषित कर दिया है। यही नहीं लिखित रूप से नोटिफाई भी किया है। इसलिए भारत सरकार की तरफ से भारतीय शिक्षा बोर्ड को पूरी तरह से मान्यता प्रदान कर दी गई है। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार के तरफ से पूरी तरह से प्रमाणित बोर्ड है।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड का मान्यता क्या है ?

भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता सेंट्रल और स्टेट बोर्ड के समकक्ष दे दी है यानी, इसका वैधानिक मान्यता दिया गया है। इसलिए अब जैसे CBSE और ICSE का मान्यताएं बोर्ड से लिया जाता था और सभी राज्य की सरकारें उनको NOC देती थी वही प्रक्रिया भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में भी अपनाया जाएगा।

### हम अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में क्यों पढ़ाएं ?

स्वामी रामदेव ने पहले ही संकेत दिये थे भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाने से हमारे बच्चों के अंदर भारत का बोध होगा, भारत के संस्कृति अध्यात्म, वेद, पुराण की जानकारी होगी और वो सिर्फ पैसे कमाने का मशीन नहीं बनेंगे बल्कि इस बोर्ड में पढ़े हुए बच्चे पूरी तरह से संस्कारित और अपने देश और धर्म के प्रति जागरूक होंगे।

आज के समय में पूरी दुनिया यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय संस्कृति एवं विकास के प्रति आकर्षित है एवं मुरीद है एवं उसकी नकल करना चाहती है लेकिन 13 वी शताब्दी तक यूरोप भी अंधकार के युग में था।

यूरोपीय लोग 14 वी शताब्दी के बाद जब रोम एवं यूनान के उन प्राचीन दार्शनिकों के जो सुक्रान प्लुटो और अरस्तु थे उनके दार्शनिक परंपरा का पुनः नवीन परिवेश के साथ मूल्यांकन अध्ययन करना शुरू किया तब जाकर एक समर्थ यूरोप का उदय हुआ।

कहने का मतलब ये है कि जब तक कोई भी समाज अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण, संवर्धन के प्रति सतर्क नहीं हो जाता वह समाज और राष्ट्र एक शक्तिशाली के रूप में कभी भी उभर नहीं सकता इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड जरूरी है। भारत के बौद्धिक संपदा में इतना ज्यादा सामर्थ्य है कि हम ऊंचाइयों को छू



सकते थे लेकिन मैकाले के द्वारा लाया गया गलत शिक्षा व्यवस्था के कारण ही हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए हैं।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड का नया फ्रेमवर्क ?

भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारत की जो नई शिक्षा नीति है जो नेशनल फ्रेमवर्क है अभी तक 2005 का चल रहा है लेकिन अब 2020 के नई शिक्षा पद्धति के आधार पर नया फ्रेमवर्क आना शुरू हो गया है। उसके अनुरूप ही उसमें जो कुछ भी अनुषोध्य मूल्य बोध हैं जो भी इवैल्यूएशन है जो भी लर्निंग आब्जेक्टिव है जो टेक्स मुक्त का प्रारूप है जो कैरिकुलम और सिलेबस का मोड़ है उस को ध्यान में रखते हुए ही लेकिन इससे भी एक कदम आगे ये भाव रखा गया है कि हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में विश्वरूप से नेतृत्व प्रदान करने के लिए समर्थ हो।

भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे भारत के जड़ों के साथ में खड़े रहेंगे और भारत के संस्कृति मूल्यों के साथ जोड़कर आगे बढ़ेंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड में बच्चों के पढ़ने का फायदा ये है कि वो सिर्फ ऊँचाईयों को छू कर आसमान में फर्क फराते ना रहे बल्कि हमें अपना जमीन भी मालूम होना चाहिए। जिस राष्ट्र के बच्चे अपने सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े नहीं होते हैं वो आंधियों और तूफानों में ढह जाते हैं इसलिए देश के बच्चों को अपने देश के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए ही भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

### पुस्तकें कब तक आएंगी ?

भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर के भी स्कूल एजुकेशन के जो अच्छी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के उच्च कोटि के शिक्षक शिक्षिकाओं को भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुस्तकों को तैयार करने में लगाया गया है। हर विषय में समूह बनाकर उसके अनुरूप पुस्तकों को तैयार करने का प्रक्रिया चालू किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च 2023 तक भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुस्तकें आने आरंभ हो जाएंगे। मार्च 2023 तक नर्सरी से लेकर आठवीं कक्षा तक के पुस्तकों को तैयार कर लिया जाएगा ऐसा माना जा रहा है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुस्तकों में भारत के वेद और वेदानुकूल शास्त्रों आदिवासी भाषाओं के शास्त्रों और दक्षिण भारत के तमिल और कन्नड़ तेलुगु मलयालम के शास्त्रों का अध्ययन किया जा रहा है इसलिए पुस्तकें आने में इतना समय लग रहा है।

### संस्कृत अनिवार्य है

भारतीय शिक्षा बोर्ड के पुस्तकों में पहली क्लास से लेकर 12वीं तक संस्कृत भाषा को

## विदेह बने ब्यूरोक्रेट

‘अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः।

स संन्यासी च योगी च न निरग्निरन चाक्रियः।’

गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता है और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है। वही संन्यासी और योगी कहलाता है।

यह कथ्य डा. एन पी सिंह पर सत्य प्रतीत होता है। विषपायी आशुतोष शिव के प्रसाद नागेंद्र प्रसाद में सिंहत्व (स्वयमेव मृगेन्द्रता) भी है अर्थात् लक्ष्य के प्रति एकाग्रता और संकल्प के प्रति दृढ़ता है। बतौर आईएएस अधिकारी डा. सिंह जिस पद पर भी रहे, वहीं अपनी जन सेवा और संवेदनशीलता की छाप छोड़ी। अगाध मेधा के धनी डा. सिंह प्रशासनिक अधिकारी के रूप में युगांतरकारी निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जन सरोकारों के प्रति इतने प्रतिबद्ध कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं।

रिटायरमेंट के बाद डा. सिंह ‘तेन त्यक्तेन भुंजीथा’ का अनुसरण करते हुए पद्म-पत्रवत जीवन जी रहे हैं। उदभट विद्वान राजा जनक अपने स्थूल शरीर से अलग होकर अनासक्त भाव से जीवन जीते थे। देह धारण करते हुए भी विदेह थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा-‘हर समय और हर देश में, पुजारी अपनी कमर कसते हैं और प्राचीन रीति-रिवाजों और प्रथाओं को संरक्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं। जनक जैसे राजा भी खड़े होते हैं, जो क्षत्रिय कौशल के साथ-साथ आध्यात्मिक शक्ति से समर्थित होते हैं।’

सांसारिक संबंधों से विरत होकर डा. सिंह शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति की अलख जगाने में रत हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर रहे हैं, जिसमें सनातन को नूतन से जोड़कर विद्यार्थियों में भारत व भारतीयता के भाव जगाकर पवित्र चरित्र व व्यक्तित्वयुक्त नेतृत्व का निर्माण करना है। विद्यार्थियों में आत्म बोध और आत्म गौरव जागृत करने वाली शिक्षा व्यवस्था स्वस्थ समाज और राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगी।

समाज सेवा, योग, ध्यान के प्रति समर्पित डा. सिंह पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर, हरिद्वार में रहकर गुरुकुलीय और सनातन शिक्षा पद्धति को अधुनातन से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आदिवासियों के लिए एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की है। इसमें शिक्षा, आवास, यूनिफार्म, भोजन सब कुछ निशुल्क है। इसके अलावा अपने गांव में भी लड़कियों के लिए मुफ्त आवासीय विद्यालय और आईटीआई कालेज का संचालन कर रहे हैं। उनमें अपने सेवाकाल से ही समाज के सेवा की ललक थी। यह लगन आज भी है। विज्ञान में एमएससी शिक्षा प्राप्त डा. सिंह की अभिरुचि आधुनिक विज्ञान के साथ-साथ धर्म, शास्त्र और प्राच्य विद्या में है।

काशी के वासी 2013 बैच के आईएएस अधिकारी डा. एनपी सिंह जिलाधिकारी अजामगढ़ के पद से रिटायर हुए। इससे पहले सहारनपुर, शामली और गौतमबुद्ध नगर के डीएम रहे। शासन में निदेशक गन्ना विकास के अलावा विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे।

अनिवार्य किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि भारत के बच्चे चाहे कितने भी सामर्थ्य हो जाएं लेकिन वो भारत के शास्त्रों को पढ़ें भले ही वो इंजीनियर हो जाएं डाक्टर हो जाएं या कोई और पद पर रहे।

इसमें कहा ये गया है कि सब्जेक्ट लिटरेचर नहीं होगा लेकिन संस्कृत का लिंगविस्टिक नालेज जरूरी होगा इससे होगा ये कि बच्चों को संस्कृत का सामान्य व्याकरण और संस्कृत के कुछ प्रमुख पुस्तकों साहित्य का सामान्य बोध हो सके।

### इंग्लिश भाषा में भी भारतीय संस्कृति

### होगी

अभी तक मैकाले शिक्षा पद्धति में इंग्लिश भाषा में यूरोप के पुष्टभूमि से परियों की कहानियां हुआ करती है, लेकिन अब भारतीय शिक्षा बोर्ड में जो इंग्लिश की पुस्तकें होगी उसने दिए गए कहानियों में भरतमुनि के नाटक लिखे जाएंगे उपनिषदों के कथा लिखे जाएंगे।

यही नहीं, इन इंग्लिश के पुस्तकों में महाभारत और रामायण के मूल्य बोध प्रेषित करने वाले संप्रेषित समुच्चय होंगे। इतना ही नहीं बुद्ध एवं जैन धर्म के जातक कथाओं में भारत के जो सांस्कृतिक आत्मा छुपी हुई है

उसका बौद्ध होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड के इंग्लिश के पुस्तकों में।

भारत में आदिवासी समाज द्वारा जो उच्च कोटि के काम किए गए हैं उसे भी इंग्लिश के पुस्तकों में स्थान दिया जाएगा।

### इतिहास में भी बदलाव होगा

भारतीय शिक्षा बोर्ड में इतिहास के पुस्तकों में बदलाव किया जाएगा क्योंकि पहले के इतिहास के पुस्तकों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया गया है और जो जानकारी महत्वपूर्ण थी उसे इतिहास में जगह देना चाहिए था उसे नहीं दिया गया और जिसे नहीं देना चाहिए उसे बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है ऐसा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा बोर्ड में इतिहास के पुस्तकों को पढ़कर भारत के बच्चे भारत के समूची ऐतिहासिक यात्रा को पढ़ते हुए अखंड भारत का ज्ञान ले पाएंगे।

वर्तमान में इतिहास के पुस्तकों में भारत के हजारों साल के प्राचीन ज्ञान की परंपरा को बहुत ही कम जगह दिया गया है और 11वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के इतिहास को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के इतिहास के पुस्तकों को पढ़ने के बाद बच्चों को ये बोध होगा कि वो एक पराजित राष्ट्र के नागरिक नहीं हैं बल्कि एक निरंतर संघर्षशील सनातन संस्कृति के प्रतीक और उसके बोध के साथ-साथ समर्थ के साथ युक्त अखंड व्यक्तित्व हो।

विलडोरान्ड का कहना था कि भारत विश्व की समस्त संस्कृतियों की जननी है। संस्कृत समस्त भाषाओं की मां होती है इसलिए इसमें हुए गलतियों को सुधारना भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए एक उच्च प्राथमिकता है।

### भारतीय शिक्षा बोर्ड से 5 लाख स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य

स्वामी रामदेव जी के अनुसार भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को पहले एक लाख और फिर 5 लाख विद्यालयों में पढ़ाए जाएं इससे होगा ये की उन 5 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 5 करोड़ बच्चों में ऐसा व्यक्तित्व, चरित्र एवं नेतृत्व बनेगा की यह बच्चे भारत को इतना ऊंचा उठा देंगे कि भारत जैसा कोई देश दुनिया में नहीं होगा और भारत सभी देशों का नेतृत्व करेगा।

इसके लिए हर जिला, हर तहसील में स्कूलों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा और स्वामी रामदेव का कहना है कि ये काम बच्चों के अभिभावक कर सकते हैं वो ऐसे कि वो अपने स्कूलों में ये मांग कर सकते हैं कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से स्कूल को जोड़ें और उसका पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए।

किसी भी स्कूल में जब ज्यादा से ज्यादा अभिभावक उस स्कूल को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ने का आग्रह करेंगे तो हो सकता है कि उस स्कूल को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ दिया जाए और ऐसे करके पहले एक लाख और फिर 5 लाख स्कूलों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष योग गुरु स्वामी रामदेव हैं। इन्होंने ही सीबीएसई के तर्ज पर मैकाले शिक्षा पद्धति के दोषपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए शिक्षा का स्वदेशीकरण हेतु भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहल की थी। स्वामी रामदेव ने सन 2015 में ही सरकार के समक्ष भारतीय शिक्षा बोर्ड का विचार स्पष्ट किया था और तब से ही इस पर काम चल रहा था। अभी कुछ ही दिन पहले मार्च 2023 को भारतीय शिक्षा बोर्ड को भारत सरकार के तरफ से मान्यता एवं अप्रूवल दे दिया गया है।

संस्कार विहीन शिक्षा से डा. अदनान अली, अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन, जैश ए मुहम्मद से जुड़ा अफजाल गुरु, खालिस्तान के समर्थक या भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। ये सभी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। छान्दोग्य उपनिषद में ऋषि नारद उस समय के प्रतिष्ठित विद्वान सनत कुमार के पास पहुंचे। कहा कि मैं बहुत अशांत और उद्विग्न हूं। हमारा मार्गदर्शन करें। सनत कुमार ने पूछा तुमने क्या क्या पढ़ा है? नारद ने कहा मैंने वेद पढ़े हैं, व्याकरण पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, निरुक्त, भूगर्भ विद्या, खगोल विद्या, विज्ञान, समाज विज्ञान पढ़ा है। ऐसे तमाम विद्याओं को पढ़कर भी नारद अशांत थे। सनत कुमार ने कहा 'ये सारी विद्याएं नाम और संज्ञा हैं। वाणी इससे बड़ी है। वाणी से बल बढ़ा है। आशा उससे बड़ी है। लेकिन ये सब अल्प और अपूर्ण हैं। सांस्कृतिक संपूर्णता के ज्ञान से सुख मिलता है।'।



छत्तीसगढ़ के बस्तर में डॉ. राजाराम त्रिपाठी संयोजक भारतीय किसान यूनियन के द्वारा मीडिया मंच का हुआ विमोचन।



## 12 जिलों के डीएम की रैंकिंग

प्रदेश के 12 जिलों के डीएम अच्छा काम कर रहे हैं। जिन्हें रैंकिंग में उन्हें टॉप 12 में स्थान दिया गया है। 75 जिलों के मूल्यांकन में अयोध्या की डीएम सबसे फिसड्डी साबित हुए हैं। जबकि फर्रुखाबाद व रामपुर के डीएम को 73वां व 74वां स्थान मिला है। जुलाई की रैंकिंग में पीलीभीत, सोनभद्र, गौतमबुद्धनगर, हमीरपुर, भदोही व बलरामपुर के डीएम को 130 में से 128 अंक प्राप्त हुए थे।

इसके आधार उन्हें रैंक वन दी गई है। वहीं खीरी, शाहजहांपुर, बरेली, बागपत, फिरोजाबाद व महोबा के डीएम को 127 अंक हासिल करने पर सातवीं रैंक दी गई है। इसी तरह अयोध्या, रामपुर, फर्रुखाबाद के डीएम क्रमशः 112, 115 व 118 अंक हासिल करके नीचे से तीन स्थानों पर आए हैं।

ललितपुर, आगरा, मुरादाबाद, कुशीनगर और कन्नौज के डीएम को 119-119 अंक मिले हैं।

**रैंक वन** पाने वाले 6 जिलाधिकारी- पीलीभीत, सोनभद्र, हमीरपुर, गौतमबुद्धनगर, भदोही व बलरामपुर हैं।

**रैंक सात** पाने वाले 6 जिलाधिकारी- लखीमपुरखीरी, शाहजहांपुर, बरेली, बागपत, फिरोजाबाद व महोबा।

**रैंक 13** पाने वाले 9 जिलाधिकारी - रायबरेली, झांसी, मिर्जापुर, इटावा, अलीगढ़, बहराइच, कौशांबी, मैनपुरी व बांदा।

**रैंक 22** पाने वाले 8 जिलाधिकारी- चंदौली, बदायूं, बलिया, गोंडा, अंबेडकरनगर, प्रयागराज, उन्नाव व अमेठी।

**रैंक 30** पाने वाले 17 जिलाधिकारी - गाजियाबाद, प्रतापगढ़, बुलंदशहर, बस्ती, मथुरा, मेरठ, सहारनपुर, सीतापुर, अमरोहा, जौनपुर, कासगंज, औरैया, श्रावस्ती, बाराबंकी, आजमगढ़ व हापुड़।

**रैंक 46** पाने वाले 6 जिलाधिकारी - संतकबीर नगर, मुजफ्फरनगर, चित्रकूट, महाराजगंज, एटा व गाजीपुर।

**रैंक 52** पाने वाले 9 जिलाधिकारी - हाथरस, हरदोई, सिद्धार्थनगर, शामली, कानपुर शहर, लखनऊ, देवरिया, बिजनौर व संभल।

**रैंक 61** पाने वाले सात जिलाधिकारी- जालौन, गोरखपुर, फतेहपुर, मऊ, वाराणसी, कानपुर देहात व सुल्तानपुर।

**रैंक 68** पाने वाले जिलाधिकारी - ललितपुर, आगरा, मुरादाबाद, कुशीनगर व कन्नौज। रामपुर 74 और अयोध्या 75।

## पीसीएस-2023 की मुख्य परीक्षा

### अब 26 सितंबर से होगी

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस)-2023 की मुख्य परीक्षा के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव के तहत पहले घोषित 23 सितंबर की परीक्षा अब 26 सितंबर से शुरू होगी।

संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के कारण पीसीएस मेन्स की परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। यद्यपि यूपीपीएससी ने अपने कैलेंडर में पीसीएस-2023 की मुख्य परीक्षा 23 सितंबर से ही प्रस्तावित की थी। आयोग के सचिव के अनुसार 15 से 24 सितंबर तक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा का आयोजन होने के कारण पीसीएस की मुख्य परीक्षा 26 से 29 सितंबर तक आयोजित की जाएगी।

## कैबिनेट सचिव राजीव को फिर मिला सेवाविस्तार



मोदी सरकार की कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का और कार्यविस्तार मिल गया है। अब वे 2024 चुनाव तक इस पद पर बने रहेंगे।

उन्हें 2019 में भारत का कैबिनेट सचिव बनाया गया था। इससे पहले वह भारत के गृह सचिव के पद पर भी थे। उन्हें पहले भी दो बार सचिव के पद पर सेवाविस्तार मिला था।

1982 बैच के झारखंड कॉर्डर के आईएएस के नेतृत्व में ही जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाने का ड्राफ्ट बनाया गया था। कैबिनेट सचिव का पद ब्यूरोक्रेट्स में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।

## पीसीएस एसोसिएशन ने की दिवंगत साथी की सहायता

पीसीएस एसोसिएशन ने अपने दिवंगत पीसीएस साथी सुनील कुमार मिश्रा के परिवार को 12 लाख 35 हजार का चेक प्रदान कर आर्थिक सहायता दी।

उल्लेखनीय है कि अपर आयुक्त द्वितीय प्रयागराज मंडल सुनील कुमार मिश्रा का निधन सेवाकाल के ही दौरान विगत 13 जून 2023 को हो गया था।

पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अपर आयुक्त-प्रथम प्रयागराज मंडल पुष्परज सिंह ने सुनील कुमार के पुत्र उत्कर्ष



मिश्रा एवं पुत्री सुश्री साक्षी मिश्रा को चेक प्रदान करते हुए दोनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

## मंजिल सैनी को मिली क्लीनचिट

आईपीएस मंजिल सैनी को विभागीय जांच में क्लीनचिट मिलने के बाद शासन ने उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच को खत्म कर दिया है। इससे अब उनकी प्रोन्नति का रास्ता सु हो गया है।

गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मंजिल सैनी के खिलाफ जांच अब खत्म कर दी गई है। वर्तमान में मंजिल सैनी एनएसजी में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं।

उल्लेखनीय है कि राजधानी के बहुचर्चित श्रवण साहू हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में यह उल्लेख किया था कि बार-बार श्रवण साहू द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की गुहार के बावजूद तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी ने श्रवण साहू को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। इसी के चलते सीबीआई ने तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी के अलावा डीएम गौरीशंकर प्रियदर्शी के खिलाफ विभागीय जांच करने की सिफारिश की थी।

इसी के चलते एडीजी इंटेलेजेंस भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में दो सदस्यीय जांच समिति गठित की गई थी। समिति ने इस घटनाक्रम से संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए।



इसमें यह निष्कर्ष उभर कर आया कि मंजिल सैनी ने अपने मातहतों से श्रवण साहू को सुरक्षा देने को कहा था। लेकिन मंजिल सैनी की गलती यह रही कि यह सब उन्होंने मौखिक रूप से कहा था। लिखित रूप में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया। बयान देने वालों में श्रवण साहू का बेटा भी शामिल था।

तेल कारोबारी श्रवण साहू की हत्या एक फरवरी 2017 को बदमाश अकील ने करवा दी थी। श्रवण 17 महीने पहले हुई बेटे आयुष की हत्या के मामले में आरोपित अकील के खिलाफ पेरवी कर रहे थे।

## ई-आफिस का पहला जिला कन्वोज



ई-आफिस लागू करने वाला कन्वोज यूपी का पहला जिला बन गया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी शुभांत शुक्ला व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। ई-आफिस सरकारी कार्यालयों में सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। इसकी लागू होने से समय की बचत होगी।

दस्तावेजों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की झंझट से मिलेगी मुक्ति। विगत 14 अगस्त से सभी कार्रवाई पूरी कर ई-आफिस प्रणाली को कलेक्ट्रेट में लागू कर दिया गया है।

## आईएएस रानू साहू मनी लाइटिंग केस में गई जेल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लाइटिंग केस में छत्तीसगढ़ की आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार किया है।

छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार होने वाली वह दूसरी आईएएस अधिकारी हैं। इनसे पहले आईएएस समीर विश्णोई की गिरफ्तारी हुई थी। विश्णोई को शराब घोटाले में गिरफ्तार होना पड़ा था।

2010 बैच की आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी कोयला घोटाले में हुई है। इस समय वह कृषि विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थीं। इससे पहले वह कोरबा और रायगढ़ जिले में कलेक्टर भी रहीं। कोयला लेबी घोटाले में ईडी ने पहले भी साहू से जुड़े रायपुर के परिसरों में तलाशी ली थी और उनकी संपत्ति भी जब्त की थी।

पहले ईडी ने रानू साहू को तीन दिन की



रिमांड पर लिया था। रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने उन्हें जूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान ईडी के अधिकारियों ने रानू साहू से मिली डायरी, मोबाइल चैट के बारे में पूछताछ की।

उल्लेखनीय है कि रानू साहू के पति जय प्रकाश मोर्य भी 2010 बैच के आईएएस अफसर हैं।

## आईएएस अदिति सिंह केन्द्र के लिए कार्यमुक्त

राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी अदिति सिंह को केन्द्र के लिए कार्यमुक्त कर दिया। उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति मिली है।



कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिया था। अदिति सिंह 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। सेन्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत उनकी नियुक्ति फिलहाल पांच साल के लिए हुई है।



# चुनौतियां ही आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी : योगी



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉडर के 2021 बैच के ट्रेनी आईएएस अधिकारियों से मुलाकात में युवा अधिकारियों को सफल कैरियर के लिए संवाद और समन्वय और सकारात्मकता का मंत्र दिया।

उन्होंने कहा कि यूपी जैसे बड़े राज्य के प्रशासन महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चुनौतियों भरा है। यह चुनौतियां ही आपके व्यक्तित्व को निखारेंगी। आपके तबादले से अगर लोग दुःखी

होते हैं तो समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती पांच-छह वर्ष में आपके काम करने की दिशा आने वाले 30-35 वर्षों के लिए आपके कैरियर की राह तय करने वाली होगी। फील्ड में तैनाती के दौरान जनता से जितना बेहतर कनेक्ट रखेंगे उतना ही लोग आपको याद रखेंगे। आप में मेरिट के आधार पर निर्णय लेने की जितनी अच्छी क्षमता होगी, उतना ही लोग आपको याद

रखेंगे। इसलिए अपनी मेधा और प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। सकारात्मक भाव से काम कर जनविश्वास अर्जित करें।

आईएएस अधिकारी के रूप में आप सभी को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर शासन के शीर्ष पदों पर काम करने का, नीतियां बनाने का दायित्व मिलेगा। ऐसे अवसर पर आपके मन में जनहित का भाव होना चाहिए।

## डॉ. अरुणवीर सिंह को फिर मिला सेवाविस्तार



पूर्व आईएएस डॉ. अरुणवीर सिंह को उनके अच्छे कार्यों के लिए एक बार फिर सेवाविस्तार

का अवसर राज्य सरकार ने प्रदान किया है।

डॉ. अरुणवीर सिंह अभी तक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के पद पर एक वर्ष के लिए पुनर्सेवायोजित थे। उनका कार्यकाल अब खत्म हो चला था।

अब शासन के अग्रिम आदेशों के अनुसार डॉ. अरुणवीर सिंह 14 जुलाई 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर पुनः बने रहेंगे। शासन के इस आदेश को राज्यपाल ने भी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है।

## लक्ष्मी सिंह को उत्कृष्ट सेवा पदक

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को गृहमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा जाएगा। गृहमंत्री भारत सरकार 9 एमएम पिस्टल और उत्कृष्ट सेवा पदक देंगे। लक्ष्मी सिंह लखनऊ परिक्षेत्र की पुलिस महानिदेशक भी रह चुकी हैं। तैनाती के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामले अपनी सूझबूझ व सतर्कता से हल किए थे। 2000 बैच की आईपीएस लक्ष्मी सिंह बीटेक-मैकेनिकल इंजीनियर व समाजशास्त्र से परास्नातक हैं।



# अच्छे अफसरों को मिल रहा काम का इनाम

## अरविंद बने नियामक आयोग के अध्यक्ष, अनुभव का मिला फायदा

योगी सरकार में अधिकारियों की अनदेखी नहीं बल्कि उन्हें उनके अच्छे काम पर इनाम भी मिल रहा है। कई आईएएस अफसरों को रिटायरमेंट के बाद घर नहीं बैठना पड़ा है। बल्कि उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए उन्हें नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया है।

जानकारों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सलाहकार आदि समेत कई पदों की जिम्मेदारी देकर उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव का इस्तेमाल करने की मंशा है। रिटायरमेंट के बाद नई पारी की शुरुआत करने वालों में अरविंद कुमार सबसे पहले हैं। उनसे पहले अवनीश कुमार अवस्थी, राजीव कुमार एवं सुरेश चंद्रा आदि हैं।

अरविंद कुमार को नियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष आरपी सिंह का कार्यकाल विगत 30 जून को पूरा हो



अरविंद कुमार



अवनीश कुमार अवस्थी



राजीव कुमार

जाने के बाद यह पद अब तक खाली थी। इस पद के लिए कई वरिष्ठ आईएएस दावेदार थे। लेकिन 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अरविंद कुमार को उनके अनुभव और साफ सुथरी छवि का लाभ मिला। यद्यपि इससे पहले फरवरी में सेवानिवृत्त होने के बाद अरविंद कुमार को योगी आदित्यनाथ ने अपना सलाहकार बनाया था और उन्हें औद्योगिक विकास सेक्टर की जिम्मेदारी दी थी। इससे पहले 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अवनीश अवस्थी को

रिटायरमेंट के कुछ महीनों बाद ही सीएम योगी का सलाहकार बनाया गया था। इसी तरह रिटायरमेंट से कुछ समय पहले आईएएस सुरेश चंद्रा का चयन राज्य सेवा लोक अधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर किया गया था।

इसी तरह 2017 में योगी सरकार बनने के बाद मुख्य सचिव के पद पर तैनात रहे राजीव कुमार जब रिटायर हुए तो उन्हें रेरा का चेयरमैन बनाया गया। अब राजीव कुमार रिटायर भी हो चुके हैं।

## 26 पीपीएस को सितंबर में मिलेगा आईपीएस का तोहफा

उत्तर प्रदेश प्रांतीय पुलिस सेवा के 1993 और 1994 बैच के 26 पीपीएस अधिकारी 21 अगस्त को आईपीएस अधिकारी बन जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 28 पदों के लिए डीपीसी होनी है। लेकिन दो अफसरों का लिफाफा बंद होने के चलते केवल 26 पदों के लिए ही डीपीसी होगी। इसमें 1993 बैच के कुल 16 और 1994 बैच के 10 अफसर शामिल हैं। डीपीसी में सभी अफसरों का सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद उनकी फाइल केन्द्रिय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी।

1993 बैच के जो अफसर पीपीएस से आईपीएस बनेंगे उनमें प्रदीप कुमार, विपुल श्रीवास्तव, हरगोविन्द मिश्रा, पंकज, विद्यासागर मिश्र, घनश्याम, आनंद कुमार, राजेश कुमार, राम सुरेश, मोहम्मद तारिक, रवि शंकर, डॉ. एम. पी. सिंह, निधि सोनकर, बसंत लाल, सुशील कुमार और देवेन्द्र भूषण शामिल हैं।

इसी प्रकार 1994 बैच के पीपीएस अफसर जो आईपीएस बनेंगे, उनमें आशुतोष मिश्रा, डॉ. राजीव दीक्षित, कुंवर ज्ञानंजय सिंह, राम नयन सिंह, आशुतोष द्विवेदी, अरुण कुमार सिंह, डॉ. दुर्गेश कुमार मधेशिया, विनोद कुमार



पांडे, नीरज कुमार पांडे और सुरेन्द्र नाथ तिवारी प्रमुख हैं। 1989 बैच के अमित मिश्रा और 1993 बैच के संजय यादव का लिफाफा बंद है। उन अफसरों का लिफाफा बंद होता जिनके ऊपर कोई विभागीय जांच चल रही है। किसी मामले

में चार्जशीट फाइल हो, दीर्घदंड हो, विजिलेंस की जांच अगर किसी अफसर के खिलाफ चल रही हो तब लिफाफा बंद हो जाता है।

अमित मिश्रा की एंटी करप्शन यूनिट में तैनाती के दौरान एक डॉक्टर को रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मगर आरोप है कि उसने रिश्तत की रकम चबाने की कोशिश की और नोट गले में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई। जिसकी जांच अभी तक चल रही है। इसी तरह संजय यादव की बलिया में तैनाती के दौरान उनकी गाड़ी को राजस्थान के एंटी करप्शन यूनिट ने चित्तौड़गढ़ से अफीम की तस्करी में पकड़ा था। यही नहीं गाड़ी में से 16 लाख रुपये भी मिठाई के डिब्बों में बरामद हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 2021 में निलंबित किया था।

बता दें कि आईएएस और आईपीएस ग्रेड में प्रमोशन के लिए अधिकतम उम्र 56 वर्ष है।



# निगाहें नवनीत सहगल की दूसरी पारी पर

प्रदेश के सर्वाधिक चर्चित आईएएस अफसरों में से एक और साथ ही तेजतर्रार छवि वाले नवनीत सहगल लगभग 35 वर्षों की लंबी प्रशासनिक सेवा के बाद रिटायर हो गए। जिस सक्रियता और तत्परता के साथ ब्यूरोक्रेसी में अपनी अलग पहचान बनाकर हर दल की सरकार में अपनी उपयोगिता और अनिवार्यता साबित करने वाले नवनीत सहगल की दूसरी पारी किस रूप में होगी, इसको लेकर कयास का दौर चल निकला है।

यह तो तय है कि जिस तरह की उनकी कार्यशैली और कर्मठता रही है उसको देखते हुए वह सन्ध्या और विश्राम की दुनिया से निश्चित रूप से दूर ही रहेंगे। वह शांत और चुप बैठने वाले ब्यूरोक्रेट नहीं रहे हैं।

वैसे उनकी दूसरी पारी का आगाज किस रूप में होगा इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें से एक यह है कि वह भी दूसरे ब्यूरोक्रेटों की तरह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सियासी पारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वह किस दल या किस पार्टी से साथ होंगे यह तो अभी कह पाना मुश्किल है और उन्होंने ने भी एक बार यही कहा था कि वह अपनी दूसरी पारी में चाहे जो कुछ भी करें लेकिन उनका समाज सेवा करने का अभियान जारी ही रहेगा। यह तो तय है कि वह चुपचाप न बैठेंगे, न ही नेपथ्य में रहेंगे।

कम बैक और क्राइसेस मैनेजमेंट में माहिर नवनीत सहगल हर सरकार में चाहे वह मायावती की सरकार रही हो या अखिलेश की सरकार हो या फिर योगी आदित्यनाथ की

सरकार ही क्यों न हो। वह सबसे साथ बेहतर जुगलबंदी के साथ न केवल अहम पदों पर ही बैठे बल्कि औरों से बेहतर नतीजे भी दिए हैं।

भले ही वह पंजाब में लुधियाना के रहने वाले रहे हैं लेकिन वह यूपी काँडर के 1988 बैच के अफसर बनकर यूपी में ही रहे और पावर सेंटर के रूप में नजर आते रहे। वह अनेकों विभागों में रहे। तीन मई 2002 को जब मायावती तीसरी बार मुख्यमंत्री बनीं थीं तो सहगल को वाराणसी से लखनऊ का डीएम बना दिया गया था। यद्यपि ढाई महीने बाद ही वनवास के तौर पर राजस्व परिषद भेजे गए लेकिन जल्द ही वह फिर से लखनऊ के डीएम की कुर्सी पर बैठने में सफल रहे।

मुलायम सिंह की सरकार में भी वह किनारे जरूर किए गए फिर वह 2005 में केन्द्रिय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली चले गए। लेकिन 2007 में जब मायावती सत्ता में लौटीं तो वह पुनः यूपी लौट आए और सचिव के तौर पर उनकी सीधी एंड्री मुख्यमंत्री कार्यालय में हो गई। इसके बाद तो वह कई अहम विभागों मसलन शहरी विकास, ऊर्जा, यूपीएसआईडीसी जैसे विभागों में रहकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे।

अखिलेश सरकार में भी वह पहले साइड लाइन किए गए लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी



उपयोगिता से सूचना जैसा अहम विभाग संभाल लिया। मुख्यमंत्री योगी की पहली पारी में भी सहगल अहम विभाग संभालते रहे। लेकिन योगी के दूसरे कार्यकाल में वह अपना रूतबा कायम नहीं रख सके और उन्हें खेल महकमे में भेज दिया गया। लेकिन यहां भी अपर मुख्य सचिव खेल के रूप में खेल विभाग को चर्चित विभागों के तौर पर पहचान दिलाने में बड़ी कामयाबी हासिल की।

विभिन्न खेल संगठनों से जुड़े सहगल ने अपनी कामयाब सेवा के तौर पर प्रदेश में पहली बार खेलनीति बनवाने में सफलता हासिल की। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के रूप में पहली बार प्रदेश में देशभर के खिलाड़ियों का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ संभव हो सका।

## प्राची सिंह को डीजी गोल्ड मेडल

बेहद तेज तर्रार और कर्मठ आईपीएस अफसर प्राची सिंह को पुलिस महानिदेशक ने गोल्ड मेडल के लिए चयन किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती में तैनात प्राची सिंह लखनऊ में एडीसीपी रहते हुए अपनी कुशलता का परिचय दे दिया था। इसी का परिणाम था कि जब युवा आईपीएस अफसर प्राची सिंह ने जब श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक रूप में कार्यभार ग्रहण किया, अपराधियों और गैर कानूनी कार्य करने वाले भयभीत हो गए।

लॉ कॉलेज भोपाल से एलएलएम करने के बाद प्राची सिंह ने पहली बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। पहली बार में उनका चयन आईपीएस में हो गया। उत्तर प्रदेश काँडर मिला। प्रशिक्षण के बाद पहली तैनाती राजधानी लखनऊ में हुई। जहां उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से विशिष्ट पहचान बनाया। प्राची सिंह अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व पीलीभीत रामसिंह गौतम की बेटी हैं।



# ‘भारत में जल परिवहन’ पुस्तक को राजभाषा सम्मान



## मीमडे

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राजभाषा शील्ड एवं मौलिक पुस्तक योजना के तहत वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरविंद कुमार सिंह को उनकी पुस्तक भारत में जल परिवहन के लिए सम्मानित किया गया। विज्ञान भवन में आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में यह पुरस्कार दिया गया। इस समारोह में कई सांसद, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी बंदरगाहों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।

उनकी लिखी पुस्तक भारत में जल-परिवहन भारत में नौवहन के गौरवशाली अतीत के साथ मौजूदा परिदृश्य में भविष्य की सम्भावनाओं की पड़ताल करती है। इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने किया है। सदियों तक जल परिवहन हमारे सामाजिक-आर्थिक विकास में मददगार रहा। ताकतवर जलमार्गों के तट पर वैभवशाली नगर बसे। लेखक का मानना है कि आज भी देश में कई इलाकों में लाखों लोगों की जरूरतें जल परिवहन से पूरी होती हैं। धीमी गति के बाद भी यह गरीबों के लिए जीवनरेखा बना हुआ है और आपदाओं के दौरान देसी नौकाएं तक सबसे अधिक काम आती हैं।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 7 अप्रैल 1965 को जन्में अरविंद कुमार सिंह हिंदी के प्रतिष्ठित पत्रकार और लेखक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने के

बाद पिछले साढ़े तीन दशकों से वे पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हैं। जनसत्ता दैनिक से अपना कैरियर आरंभ करने वाले अरविंद कुमार सिंह ने अमर उजाला, जनसत्ता एक्सप्रेस, हरिभूमि समेत कई अखबारों को सेवाएं दी और तीन सालों तक रेल मंत्रालय में सलाहकार भी रहे। एक दशक तक राज्य सभा टीवी में संसदीय मामलों के संपादक के तौर पर पर काम किया। राज्य सभा की मीडिया सलाहकार समिति के अलावा कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड आफ स्टडीज के सदस्य भी रहे हैं। श्री सिंह पीएम युवा कार्यक्रम के मेंटर भी रहे हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनकी 600 से अधिक रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी तथा टेलिविजन चैनलों पर 400 से अधिक कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं।

अरविंद कुमार सिंह संचार, परिवहन क्षेत्र और ग्रामीण समाज के अध्येता हैं। अरविंद सिंह कई पुस्तकों के लेखक हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित उनकी पुस्तक भारतीय डाक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तथा असमिया भाषा में प्रकाशित हुई है। डाक टिकटों में भारत दर्शन पुस्तक के अलावा उन्होंने भारतीय महिला कृषक नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम और कई राज्यों में पाठ्यक्रम में उनकी रचनाएं शामिल किया है।

श्री सिंह को भारत सरकार के साक्षरता पुरस्कार, गणेशशंकर विद्यार्थी पत्रकारिता

## भारत में जल परिवहन

अरविन्द कुमार सिंह



पुरस्कार, हिंदी अकादमी, दिल्ली द्वारा साहित्यकार सम्मान (पत्रकारिता), चौधरी चरण सिंह कृषि पत्रकारिता पुरस्कार, इफको हिंदी सेवा सम्मान, शिक्षा पुरस्कार 2009, भारतीय प्रेस परिषद के ग्रामीण पत्रकारिता में उत्कृष्टता पुरस्कार, महेश सुजन सम्मान के अलावा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की ओर सम्मानित किया जा चुका है।





छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान लखनऊ के पत्रकारों से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विधानसभा सत्र के व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से लगभग एक घंटे तक छत्तीसगढ़ के विकास एवं राजनीति पर हुई चर्चा। बेहद सरल और सहज भाव से मिले बघेल के अंदर प्रदेश के विकास की ललक दिखाई पड़ी। प्रदेश में संचालित तमाम विकास योजनाओं की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि गायों के गोबर का विपणन उनकी अनूठी योजना है। इससे गोपालकों को लाभ हो रहा है। अब राज्य सरकार गोमूत्र के विपणन का कार्य भी करने जा रही है। मुख्यमंत्री से मिलने वालों में वरिष्ठ पत्रकार टी.बी. सिंह (संपादक मीडिया मंच), सिद्धार्थ कलहंस (बिजनेस स्टैंडर्ड), रश्मि शर्मा (फ्री प्रेस जरनल), वीरेन्द्र सिंह (मीडिया मंच), राजेश मिश्रा (नवभारत), अजय त्रिवेदी (आज समाज) आदि मौजूद थे।





**मीडिया मंच के रजत जयंती वर्ष पर  
हार्दिक शुभकामनाएं**

**अंजू सिंह**  
परियोजना अधिकारी  
डूडा, संभल





**IAS RP Singh**



**IAS Shishir**



**IAS Dr. Dinesh Chandra**



**IAS Dhananjay Shukla**



**PCS Mukesh Chandra**



**PCS Dr. Arun Kr. Singh**

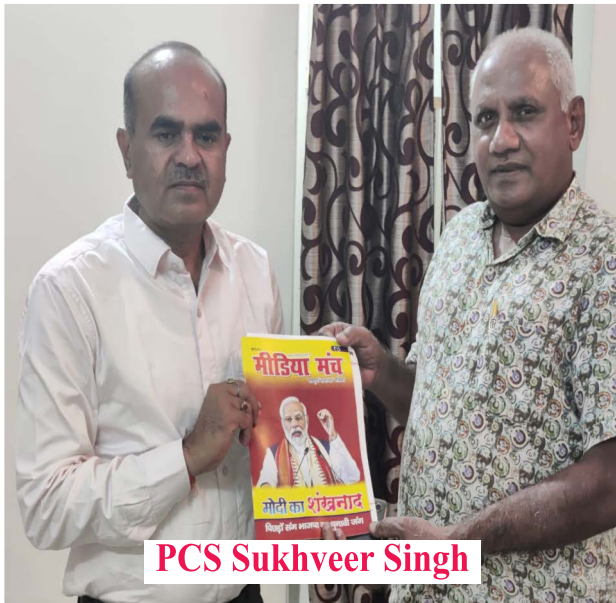




**Mritunjay Kumar**



**PCS Ritu Suhas**



**PCS Sukhveer Singh**



**Mohan Khem Chandani**



**Dr. Rajaram Tripathi**



**Adv. Apurva Tripathi**





• वीरेन्द्र शुक्ल  
9936403929



## एशियाई खेल

# बड़ा दल बड़ी आशा

स्वरूप ले चुका है। अब यह हाकी का ही मुख्य मैदान बन गया है।

पहले एशियाई खेलों के बाद फिर जाकर 1982 में भारत ने पुनः एशियाई खेलों की मेजबानी की। इन खेलों का मुख्य आयोजन स्थल नई दिल्ली का जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम था।

इस बार के 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझोउ शहर में आगामी 23 सितंबर से आयोजित हो रहे हैं। लेकिन चीन के लिए यह बड़ी बात है कि वह इस तरह तीसरी बार एशियाई देशों के सबसे बड़े खेल मेले का आयोजन करने जा रहा है। इससे पूर्व चीन में पहली बार 1990 में और फिर 2010 में गुवांगझू में एशियाई खेल हो चुके हैं।

बावजूद इसके सबसे ज्यादा बार एशियाई खेलों का मेजबान होने का गौरव थाईलैंड की राजधानी बैंकाक को है। बैंकाक में अब तक चार बार (1966, 1970, 1978 व 1998) एशियाई खेल हुए हैं। जबकि भारत की ही तरह जापान और इंडोनेशिया दो-दो बार इन

खेलों की मेजबानी कर चुके हैं। जापान में 1958 में टोक्यो में और फिर 1994 में हिरेशिमा में खेलों का आयोजन हुआ है। इंडोनेशिया में पहली बार जकार्ता में 1962 में और फिर पिछले एशियाई खेल पालेमबैंग (जकार्ता) में 2018 में हो चुके हैं।

अतीत को देखें तो अब तक हुए 18 बार हुए एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछली बार ही जकार्ता में हुआ है। जहां भारत ने 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 69 पदकों पर कब्जा किया था। खेलमंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि भारत इस बार जकार्ता से भी बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारत का एशियाई खेलों में अब तक का सबसे बड़ा खेल दल इस बार पदकों की दौड़ में होगा। खेल मंत्री के अनुसार इस बार भारत का 600 सदस्यीय दल खेलों में भाग लेगा। जबकि पिछली बार जकार्ता में 570 और उसके पहले 2014 में इंचियोन एशियाई खेलों में भारत का 570 सदस्यीय दल उतरा था। इन खेलों के लिए भारत सरकार ने बड़ी धनराशि खर्च की है।

एशियाई खेलों की चर्चा होते ही 1951 याद आ जाता है। यह वही साल है जब दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में एशियाई खेलों की मशाल जली थी। यह पहले एशियाई खेल थे। भारत को न केवल पहले एशियाई खेलों की मेजबानी का सम्मान ही प्राप्त है बल्कि उसे एशियाई खेलों की शुरुआत का भी सारा श्रेय है। यानी भारत एशियाई खेलों का जन्मदाता है।

उल्लेखनीय है कि अब एतिहासिक नेशनल स्टेडियम मेजर ध्यानचंद हाकी स्टेडियम का



खेलमंत्री अनुराग ठाकुर के अनुसार हांगझो एशियाई खेलों की तैयारियों के लिए 220 करोड़ से भी ज्यादा खर्च कर चुका है। यह जानकारी उन्होंने मिशन ओलंपिक सेल की 100वीं बैठक के बाद देते हुए कहा कि इस ओलंपिक चक्र में सरकार खिलाड़ियों की तैयारियों और उपकरणों पर 450 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। जबकि 45 करोड़ रुपये टारगेट ओलंपिक फोडियम (टैंप्स) से जुड़े खिलाड़ियों की तैयारियों और उनके प्रस्तावों पर खर्च हो चुके हैं।

भारत का एशियाई खेलों में अब तक का यह सबसे बड़ा दल चर्चित खेलों के अलावा कुरास, जु-जित्सु व शतरंज जैसे खेलों में भी हिस्सा लेगा। जहां तक शतरंज की बात है तो भारत ने सबसे पहले 2006 में जब दोहा में एशियाई खेलों में शतरंज की शुरुआत हुई थी तो कोनेरु हंपी ने महिला व्यक्तिगत और मिश्रित टीम स्वर्णम सफलता हासिल की थी। शतरंज 2014 और 2018 के एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। इस बार 36 साल की टीम की सबसे अनुभवी कोनेरु हंपी से बड़ी आशाएं हैं और वह भारतीय चुनौती की अगुवाई कर रही हैं। 10 सदस्यीय शतरंज टीम में पांच पुरुष और पांच महिला खिलाड़ी शामिल हैं।

### फुटबाल को लेकर दरियादिली

खेल मंत्रालय ने इन खेलों के लिए 15 टीम खेलों के प्रतिनिधित्व को मंजूरी दी है। इनमें क्रिकेट, कबड्डी, हाकी, बालीबाल, फुटबाल सहित कुल 15 टीम गेम हैं। महिला सॉफ्टबाल और पुरुष वाटर पोलो टीम सहित चार टीम को इस महाद्विपीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की मंजूरी नहीं दी। इसी के साथ भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने इन दोनों टीमों के अलावा पुरुष हैंडबाल और फाइव-ए-साइड बॉस्केटबाल टीम को भी हांगझो जाने से रोक दिया है। लेकिन वहीं



## अनु को मिला एशियाई का टिकट

उत्तर प्रदेश के मेरठ से ताल्लुक रखने वाली भाला फेंक एथलीट अनुरानी ने भी अपने प्रदर्शन से एशियाई खेलों का टिकट पा लिया है।

राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता अनु ने फेडरेशन कप के दौरान अपने भाले को 59.24 मीटर तक फेंक कर न केवल स्वर्ण पदक ही जीता बल्कि एशियाई खेलों में भाग लेने की पात्रता भी हासिल कर ली।

एशियाई खेलों के लिए महिला भाला फेंक का क्वालीफाइंग मार्क 56.46 मीटर है। वैसे अनु की बात करें तो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 63.82 मीटर का रहा है।



खेल मंत्रालय ने फुटबाल को लेकर बड़ी दरियादिली दिखाई है।

केन्द्रीय खेलमंत्री अनुराग ठाकुर ने नियमों में ढील देकर फुटबाल की दोनों पुरुष एवं महिला टीमों को खेलने के लिए हरी झंडी दिखाई है। खेल मंत्रालय के नियमों के अनुसार एशिया में शीर्ष आठ टीमों को ही एशियाई खेलों में भाग लेने की अनुमति है। इस मापदंड पर हाल ही में सैफ चैंपियन बनी फुटबाल टीम खरी नहीं उतरी थी। ऐसे में खेल मंत्रालय ने टीम को खेलने की अनुमति नहीं दी थी। इस पर टीम के विदेशी कोच क्रोएशिया के इगोरस्टीमेच ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने टीम को एशियाई खेलों में भेजने की गुहार लगाई थी तब जाकर बात बनी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फुटबाल टीमों की भागीदारी की पुष्टि को देश में खेल के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर बताते हुए कहा कि इससे आने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय पुरुष फुटबाल टीम को

आसान झा मिला है और उसे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। जबकि महिला टीम ग्रुप बी में थाईलैंड और चीनी ताइपे के साथ है। पुरुष टीम एशियाई फुटबाल परिसंघ में 18वें स्थान पर है। जबकि महिला टीम की एशियाई रैंकिंग 11 है। भारतीय पुरुष टीम एशियाई खेलों में दो बार स्वर्ण पदक जीत भी चुकी है।

### क्रिकेट में जीत का दावा मजबूत

एशियाई खेलों में पहली बार भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम अपनी चुनौती पेश करने जा रही हैं। पुरुषों के मुकाबले 28 सितंबर से शुरू हो रहे हैं लेकिन पुरुषों की टीम दोएम दर्जे की मानी जा रही है। वहीं 19 सितंबर से महिलाओं की स्पर्धा में हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत की मुख्य टीम भाग ले रही है।

एशियाई खेलों में अभी तक केवल तीन बार क्रिकेट के मुकाबले हुए हैं। पहली बार 1998 में बैंकाक में पुरुष क्रिकेट का आयोजन हुआ था। फिर 2010 में और 2014 में क्रिकेट के मुकाबले हुए थे। आठ सालों के बाद एशियाई खेलों में पुनः क्रिकेट की वापसी हो रही है।

15 सदस्यीय पुरुष टीम की कमान 26 वर्षीय रितुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है। टीम में उत्तर प्रदेश से दो खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें एक अलीगढ़ के रिंकू सिंह हैं तो दूसरे भदोही के यशस्वी शामिल हैं। जहां तक यशस्वी की बात है तो वह वेस्टइंडीज की धरती पर पदार्पण टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले





भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं। वहीं वह विदेशी धरती पर शतक जमाने के मामले में छठे भारतीय हैं। रिकू सिंह आईपीएल के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हैं। आईपीएल में कोलकाता के लिए खेलने वाले रिकू 14 मैचों में 474 रन बनाकर नौवें स्थान पर रहे।

टीम की कप्तानी को लेकर उत्साहित रितुराज ने कहा कि उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि टीम स्वर्ण पदक के साथ पोटियम पर खड़ी हो ताकि राष्ट्रगान बज सके। कप्तान ने कहा कि भारत के लिए खेलना वास्तव में एक गर्व की अनुभूति है और इतने बड़े आयोजन में टीम का नेतृत्व करना व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और मेरे साथ मौजूद सभी टीम सदस्यों के लिए एक बड़ा अवसर होगा।

### निशानेबाजी में 33 निशानेबाज होंगे

निशानेबाजी में इस बार 33 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। सबसे खास बात यह है कि टीम में 35 साल के जोरावर सिंह संधू (ट्रैप) और एशियाई खेलों में स्वर्ण जीत चुके एशियाई ओलंपिक परिषद (ओसीए) के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर सिंह की बेटी राजेश्वरी कुमारी (ट्रैप) ने शॉटगन शूटिंग टीम में जगह बनाई है। जबकि पेरिस ओलंपिक का कोटा दिलाने वाले भवनीश मेंदीरता, श्रेयसी सिंह और अनुभवी स्कीट शूटर मेराज अहमद खान टीम में जगह नहीं बना सके। महिला स्कीट में हाल ही में संपन्न पहली बार विश्वकप का रजत पदक जीतने वाली गनीमत शेखो और दर्शा राठौर ने टीम में जगह बनाने में सफलता हासिल की।

निशानेबाजी टीम की एक खास बात यह भी है कि पंजाब की निशानेबाज 21 वर्ष सिफत कौर ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई तक छोड़ दी। सिफत के सामने या तो डॉक्टर बनना विकल्प था या फिर देश के लिए पदक जीतना। उसने पदक जीतने के लिए डॉक्टर बनने की चाहत को तिलांजलि दे दी। माता-पिता ने भी उसका साथ दिया।

टेबल-टेनिस में पुरुषों में अंचत शरत कमल और महिलाओं में मनिका बत्रा भारत की दस सदस्यीय टीटी टीम की अगुवाई करेंगी।

तैराकी में वीर धवल खाड़े 36 सदस्यीय तैराकी दल हांगझोउ जाएगा। तैराकी में 21, डायविंग में दो और वाटर पोलो में 13 खिलाड़ी शामिल हैं। खाड़े ने 2010 के एशियाई खेलों में 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीता था। अनुभवी खाड़े के अलावा 12 सदस्यीय तैराकी टीम में साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज की जोड़ी भी शामिल है।

## कुश्ती में 'दंगल', मुक्केबाज का मसला कोर्ट में, घुड़सवारी में कोच का इस्तीफा व जूडो में डोप



एशियाई खेलों की जोरदार तैयारियों के बीच कुश्ती में चयन को लेकर मचा घमासान, जूडो में खिलाड़ियों द्वारा डोप लेने की कलंकित कर देने वाली घटनाओं के साथ ही घुड़सवारी में विदेशी कोच के इस्तीफे और मुक्केबाजी में चयन का मामला कोर्ट तक पहुंचन जैसी अशोभनीय व अप्रिय प्रकरणों ने गहरा झटका भी महसूस कराया है।

कुश्ती में तो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौनशोषण के मामले के बाद जब तदर्थ समिति ने ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता विनेश फोगाट को एशियाई खेलों में सीधे प्रवेश बिना ट्रायल के दे दिया तो दूसरे पहलवान और उनके कोचों ने इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन तक किया। इसी के साथ इस छूट ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाले पहलवानों के बीच फूट के संकेत भी दिखाई पड़ गए। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने बजरंग और विनेश को बिना ट्रायल के एशियाई की टीम में शामिल करने का साक्षी ने विरोध किया। साक्षी ने कहा कि उन्होंने भी ट्रायल में छूट देने की बात कही थी। लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। इसी के साथ एक नाटकीय घटनाक्रम भी नजर आया। जिसमें चयन ट्रायल के दौरान सबसे बड़े उलट-फेर के तौर पर टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार (47 किलोग्राम) की हार रही। इसी तरह विशाल पहलवान ने फाइनल में रोहित को हराया। लेकिन वह ट्रायल जीतकर भी टीम में जगह नहीं पाने पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही। वैसे एशियाई में भारत की तरफ से कुश्ती में 18 सदस्यीय पहलवान दल भेजे जाने हैं।

मुक्केबाजी में टीम चयन का मामला तो और भी गरमाया। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंचाल ने टीम में चयन न होने पर अदालत में चुनौती देने के साथ यह आरोप लगाया कि चयन मुकाबले पक्षपात पूर्ण रहे हैं।

जूडो की बात करें तो जूडोकाओं ने शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया। क्योंकि एशियाई खेलों के लिए चयनित आधी पुरुष जूडो टीम डोप में फंस गई। नाडा की सैंपिलिंग में कुल पांच जूडोका पाजिटिव पाए गए। जूडो टीम का प्रशिक्षण शिविर भोपाल में लगाया गया था। टीम में चयनित



एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेता मोहसिन गुलाब अली (60), जकार्ता एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले हर्षदीप बराड (81), स्टैण्डबाई राहुल सेवता (81) आदि डोप टेस्ट में फेल रहे। इस पर गुलाब का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश का यह परिणाम है।

घुड़सवारी में तो भारतीय घुड़सवारी इवेंटिंग टीम के कोच रोडोल्फ शेरेर ने महासंघ पर सहयोग न देने का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया। भारत ने 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में आशीष की कप्तानी में रजत पदक जीता।



पीयूष त्रिपाठी  
7518839758



चचा चकल्लस चहक रहे थे। पास आए और बोले देख भाई इस बार पंदरा अगस्त को मुझे भाषण देना है, अब तू मेरे को बस टापिक बता दे किस-किस टापिक पर बोलूँ कि सुनने वालों के कान से धुंआ, आंख से धुंध, नाक से धूल निकलने लगे, मैंने कहा चचा गरीबी, बेरोजगारी महंगाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी बातें हैं तो बोलने के लिए। मैं क्या बताऊँ आपको। दो दिन बाद चचा ने मुझे कुछ कागज थमाए और कहा पढ़कर देख ये लिखा है मैंने अपना भाषण। उन्होंने जो लिखा वह यूँ है। दोस्तों और दुश्मनों- इस महान देश में गरीबी आदिकाल से है- यहां के सबसे गरीब लीडर थे जवाहर लाल नेहरू के पिताजी जो अपने बेटे को इस देश में पढ़ा तक नहीं पाए। उनके बाद सर्वाधिक गरीब शख्स मैं हूँ- इस कदर गरीब हूँ कि मेरे पास अपना एक होटल तक नहीं है, खुद का सिनेमाघर, निजी प्लेन, ट्रेन, बस-स्कूल, सड़क जैसी जरूरी चीजों के लिए तरस रहा हूँ, दूसरे के होटल में रहना, खाना, पराए सिनेमाघर में फिल्में देखना, अन्य कंपनी के प्लेन में सफर करना कितना पीड़ादायक होता है, मैं ही जानता हूँ कितना, मजबूर-लाचार हूँ मैं कि अपना स्कूल तक नहीं है और तो और जुआ के खेलने के लिए दूसरे के कसीनो जाना पड़ता है।

किसी और की बनाई ऑडी कार में बैठकर मैं दूसरे के माल में दूसरे देश के आयात किया आटा लाता हूँ तब घर वालों को रोटी नसीब हो रही है ऐसी घनघोर गरीबी कई पीढ़ियों से चली आ रही है, चाहे जिसकी सरकार रही हो, गरीबी बरकरार है। मेरे घर फार्म हाउस कहीं भी अपना कोई सामान नहीं है, सब दूसरी कंपनियों के बने हैं, क्या करूँ मैं ?

बात करें रोजगार की तो मंत्री जी ने फरमाया था कि लघु उद्यम के लिए सब्सिडीयुक्त लोन मिलेगा, मैं जब लोन लेने गया तो मुझे बताया कि इस तरह आप एक फैक्ट्री के मालिक

## माख पटक कै जो बोली .....

बन जाओगे, अगली पंचवर्षीय में फिर दूसरी फैक्ट्री के, फिर तीसरी के, मैंने पूछा कि फिर क्या होगा- जवाब मिला फिर क्या। बैठे-बैठे खाओगे-मैंने कहा -वो तो मैं अब भी खा रहा हूँ, फिर काहे खोखट करूँ- अभी आवास योजना की कालोनी में निवास, फ्री राशन, आयुष्मान योजना में फ्री इलाज, लडके को वजीफा, अम्मा को वृद्धावस्था पेंशन, मेरी विकलांग पेंशन, जनधन में फ्री खाना साल में दो चुनाव में सब कुछ फ्री। रोजगार की किल्लत ही किल्लत। मेरे खानदान में किसी के पास रोजगार नहीं है। एक भाई मीडिया में है। दूसरा नेता जी का



प्रतिनिधि, तीसरा बैंक में दलाल पांच परसेंट में प्रोजेक्ट लोन कराता है, चौथा दहेज के मुकदमें में जेल में है। बहन लेडी डान है। चाची प्रधान। चाचा प्रधानपति। मेरा पूरा खानदान बेरोजगार है। हम सब शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षित और फर्जी यूनिवर्सिटी के डिप्लोमा डिग्रीधारी हैं जिसका कोई उपयोग नहीं।

सोशल मीडिया के मास्टर। फॅकने में फर्स्ट। अपनी बनाने में माहिर-दूसरे की बिगाडने में अव्वल। सुरक्षा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हमसे सुरक्षा को खतरा है, हमारी सुरक्षा कतई खतरे में नहीं है। हमारी वजह से पुलिस पीएसी होमगार्ड रखने पड़ रहे हैं। ऐसे परम पावन धनी समृद्ध देश के लिए मेरे जैसा नागरिक मिलना और उसका अपने कर्तव्यों के प्रति सत्यानाशी सोच का रखना परम सौभाग्यपूर्ण हैं।

क्योंकि यहां तो सोच नष्ट, एप्रोच भ्रष्ट, सब कार्य निकृष्ट। नागरिक पस्त, व्यवसाय ध्वस्त परिवार त्रस्त। आपाधापी भागम दौड़ी, पैसा कौड़ी के ढेर मस्त- ऐसे में हम माख पटक-पटक जो कोई बोली पंडा अगस्त। जय हिन्द-जय भारत।

### दीदी ने कहा यूपीए की ठठरी.....

अतिप्रिय, कलेजे का छिलका, दिल का टुकड़ा, प्यारा दुलारा, देश की धड़कन, पालिटिक्स का पालिथिन कुर्सियों की आंख का तारा यूपीए चल बसा। अभी तो 18 साल का भी नहीं था। हमने कितने बड़े-बड़े सपने देखे थे, कितनी उम्मीदें पाली थीं। हाय-हाय क्या करूंगा अब मैं। छाती कूटते, बाल नोचते, चीखते-चिल्लाते चचा चकल्लस बीच सड़क पर लोट रहे थे। भीड़ इकट्ठी थी, किसी ने पूछा अरे क्या हुआ चचा! चाची चल बसी क्या? चचा-चाची गरमाए चल बसी होगी तेरी-मेरा तो यूपीए चल बसा, तुम लोग समझ नहीं रहे। अभी 18 साल का था। दिल का इतना बड़ा कि देश के दर्जन भर ऐसे-गैरे-नत्थू खैरे, लबरे-झबरे, चिरकुट-चिरांयध मरियल-सडियल दलों को अपनी छतरी के नीचे रखता था, बुढ़े खूसट, अघेड़ जवान तमाम मरगैले नेताओं को पनाह देकर कुर्सियों पर बैठाता था। इतना धैर्यवान कि उसे गठबंधन के बजाय टग बंधन कहते रहे लेकिन उसने चीं तक नहीं किया। दबंग इतना कि राजग को पनपने नहीं दिया। दइया रे। मेरा “यूपीए”। चचा आयं शांय बके जा रहे थे पब्लिक भड़क उठी। चचा को उठाया, चबूतरे पर बैठाया-फिर पूछा-किसने कहा तुमसे कि यूपीए नहीं रहा चचा ने आंसू पोछते हुए बताया-दीदी ने कहा। सरे आम कहा, ललकार कर कहा कि अब यूपीए जैसा कुछ नहीं रहा। अब मेरे लिए आज की तारीख में दीदी से बढ़कर कोई नहीं है उनकी बात -ब्रम्ह वाक्य। दीदी ने कहा तो सही।

आप लोग जाइए, मुझे मातम करने दीजिए पब्लिक में कोई बोला-अमां चचा यूपीए तो 2014 में ही लकवाग्रस्त हो गया था, कोई मसाज थेरेपी, कोई पैथी काम नहीं आई। सेंक-सांठ कर जीवित रख रहे थे-आखिर जर्जर-काया, आहत मन कब तक रहता- कब तक सहता। आखिर प्रयाण कर गया। इसमें इतना रोने-चिल्लाने की बात क्या है चचा। चचा ने गुम्मा उठाया और दे मारा। पब्लिक भाग खड़ी हुई। चचा फिर रोने लगे। हाय मेरा यूपीए। लौट के आजा। यूपीए अब कब आएगा। मेरा यूपीए कितना बढ़िया था, कनिमोड़ी, ए राजा चिदंबरम, कल्माडियों को अपनी कोख में पालने वाले तुम हमेशा अमर रहोगे, जिन्दाबाद रहोगे। अरे कोई इसकी ठठरी बांधो-ले चलो। □





# यूपी में बढ़ रहे बाघ

**चार साल में संख्या 173 से बढ़कर 205 हो गई**

**दे**

शा  
में ही  
नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश

में भी बाघों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। यह सुखद स्थिति है क्योंकि एक समय चीतों की ही तरह बाघों के भी खत्म होने की की संभावना व्यक्त की जाने लगी थी।

बाघों की संख्या में बढ़ोत्तरी की एक बहुत बड़ी वजह 1973 में शुरू की गई प्रोजेक्ट टाइगर है। उस समय देश में बाघों की कुल संख्या महज 268 ही थी। यह चिन्तनीय संख्या बाघों के शिकार के चलते उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बाघों के शिकार पर प्रतिबंध लगने और उनके संरक्षण के उपायों ने स्थिति बेहतर बनाने में मदद की।

विश्व बाघ दिवस (29 जुलाई) को केन्द्रीय राज्यमंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने जिम कार्बेट रिजर्व में रिपोर्ट जारी की उसके अनुसार देश में साल 2018 में जहां 2,967 बाघ थे वहीं 2022 तक इनकी आबादी 6.8 प्रतिशत की दर से बढ़कर कम से कम 3,167 और अधिकतम 3,925 हो सकते हैं। इसलिए औसत संख्या 3,682 मानी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 785 बाघ मध्य प्रदेश में हैं। जबकि नागालैंड देश का एक ऐसा राज्य है

## कहां कितने बाघ

प्रदेश	संख्या
मध्य प्रदेश	785
कर्नाटक	563
उत्तराखंड	560
महाराष्ट्र	444
तमिलनाडु	306
उत्तर प्रदेश	205

## यहां घटे बाघ

प्रदेश	2018	2022
तेलंगाना	26	21
छत्तीसगढ़	19	17
झारखंड	05	01
ओडिशा	28	20
अरुणाचल	20	09

जहां एक भी बाघ नहीं है।

इन आंकड़ों को हर चार साल में होने वाली देश व्यापी बाघ गणना का भारतीय वन्य

जीव संस्थान के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है।

शिवालिक पर्वत व गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बाघों की आबादी में 16 साल में 275 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जो देश में सबसे ज्यादा है। इसमें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक योगदान है।

उत्तर प्रदेश में पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या में 18 फीसदी की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 63, दुधवा में 135 और रानीपुर टाइगर रिजर्व में चार बाघ हैं। प्रदेश में तीन बाघ इन रिजर्व क्षेत्रों से बाहर भी मिले हैं। यद्यपि इस गणना में बिजनौर के अमानगढ़ के जंगल के बाघों को शामिल नहीं किया गया है। चूंकि अमानगढ़ को कार्बेट पार्क का बफरजोन माना जाता है। इसलिए वहां के बाघों की गिनती कार्बेट पार्क के तहत की जाती है। यूपी में 2006 में मात्र 109 बाघ थे। और 2016 में यह संख्या 118 हुई थी। वहीं 2014 में संख्या में गिरावट हुई और 117 बाघ ही रह गए थे।

इसी तरह उत्तराखंड में साल 2006 में जहां 178 बाघ ही बचे थे वहीं आज उनकी संख्या तीन गुना बढ़कर 560 पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 260 बाघ उत्तराखंड के जिम कार्बेट रिजर्व में हैं।

इस तरह यूपी में वनों के बेहतर प्रबंधन के अच्छे नतीजे मिलने लगे हैं।



# दंडक वन प्रभु कीन्ह सुहावन



वीरेन्द्र सिंह  
9410704385



आ

ज भी दंडक वन सुहावना है। प्रचुर वन संपदा, दुर्लभ वनोपधि, अकूत खनिज भंडार से भरा है। यहां पहले राक्षसों का अत्याचार था, आज नक्सलियों का आतंक है। इनके बीच में पहले भी ऋषि-मुनि रहते थे, आज भी सज्जनों का वास है। रायपुर से दंतेवाड़ा तक लगभग 500 किलोमीटर तक यात्रा के दौरान रज-रज में राम के रमे होने का आभास हुआ। आश्चर्य हुआ इस सघन, गहन वन प्रांतर में तापस वेष धरकर राम, लक्ष्मण और सीता कैसे विचरण किए होंगे। जंगली जानवर, कंटकाकीर्ण मार्ग, राक्षसों के भय का सामना करते हुए 10 वर्ष बिताए होंगे।

रामायण और रामचरित मानस में वर्णित दंडकारण्य का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी बहुतायत से आया है। अबूझमांड की पर्वत श्रृंखलाओं और कोरापुट के पठारी मैदान में बसा 35,600 कि.मी. में फैला यह दण्डकारण्य छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, आंध्र और उड़ीसा की सीमाओं को छूता है। राम चरित मानस के अरण्य कांड में दण्डकारण्य का ही वर्णन है। दंतेवाड़ा में डाकिनी और शाकिनी राक्षसियों के नाम की दो नदियां आज भी विद्यमान हैं। मान्यता है कि 14 वर्ष के अपने वनवास के 10 साल भगवान राम ने इसी दण्डकारण्य में ही बिताए थे। रामायण महाकाव्य में तमाम ऐसे स्थानों का उल्लेख है जो आज भी दण्डकारण्य में मौजूद हैं।

पंपा सरोवर आज भी गोदावरी से थोड़ी ही दूर स्थित है। यहीं पर गीदम गांव है, जो अतीत में गिद्धम के नाम से प्रसिद्ध था। इसी जगह गिद्धराज जटायु ने सीताहरण कर ले जा रहे रावण से युद्ध करते हुए अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली थी।

किष्किंधा यहां की प्रमुख नगरी थी जो कि वानरराज सुग्रीव की राजधानी थी। बाली के छोटे भाई सुग्रीव अपने मंत्री जामवंत और सहयोगी हनुमान के साथ यहीं रहा करते थे। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजी को यहीं प्रवर्षण पर्वत पर ढहराया गया था।

पंचवटी नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास है। रावण ने देवी सीता का हरण पंचवटी से ही किया था। शूर्पणखा के प्रणय प्रस्ताव को अस्वीकार कर यहीं उसकी नाक काटी गई थी। कहते हैं कि नासिका से ही नगर का नाम नासिक पड़ा। कांकर के घने जंगलों के बीच रावण सीता का हरण करता है। जटायु सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करता है। और लड़ते-लड़ते मारा जाता है। संयोगवश जटायु का भाई संपाती रावण को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देख लेता है। इसी दण्डकारण्य में भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। नवधा भक्ति की शिक्षा दी थी। गौतम ऋषि के शाप को झेल रही शिलावत अहिल्या को पुनर्जीवित कर श्रापमुक्त किया। आज भी छत्तीसगढ़ में राम वनवास के निशान मौजूद हैं।

सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी में तीन कक्षों वाली सीताबेंगरा गुफा है। वनवास काल में राम यहां पहुंचे थे, यह सीता का कमरा था। चांपा जिले में स्थित शिवरीनारायण में रुककर भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाए थे। यहां नर-नारायण और शबरी का मंदिर भी है। भाटापारा जिले के तुरतुरिया नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं था। तुरतुरिया ही लव-कुश की जन्मस्थली थी।

रायपुर जिले के 126 तालाब वाले चंदखुरी गांव में जलसेन तालाब के बीच में भगवान राम की और माता कौशल्या का मंदिर है। कौशल्या माता का दुनिया में यह एकमात्र मंदिर है। चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है, इसलिए यह राम का ननिहाल कहलाता है। गरियाबंद जिले के राजिम को प्रयाग कहा जाता है, जहां सोंदुर, पैरी और महानदी का संगम है। कहा जाता है कि वनवास काल में राम ने इस स्थान पर अपने कुलदेवता महादेव की पूजा की थी, इसलिए यहां कुलेश्वर महाराज का मंदिर है। यहां मेला भी लगता है।

धमतरी जिले के सिहावा की विभिन्न पहाड़ियों में मुचकुंद आश्रम, अगस्त्य आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगि ऋषि, कंकर ऋषि आश्रम, शरभंग ऋषि आश्रम एवं गौतम ऋषि आश्रम



आदि सप्तर्षि आश्रम है। बस्तर जिले के जगदलपुर से वनवास काल में राम गुजरे थे, क्योंकि यहां से चित्रकोट का रास्ता जाता है। चित्रकोट जल प्रपात के पास ही उन्होंने चातुर्यमास बिताया था।

दंडकारण्य ही रक्ष-संस्कृति के विनाश का माध्यम बनी। दण्डकारण्य की भूमि शैव और शाक्त भक्ति की उपासक रही है। बस्तर की पर्वतमाला को बैलाडिला कहा जाता है। यहां की भाषा में बैलाडिला का अर्थ है-बैल का कूबड़। यह बैल ही शिव का नंदी है। दूसरी ओर दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरीदेवी मां शक्तिरूपा हैं।

## राम वन गमन पथ

राम वन गमन पथ के रास्ते में पड़ने वाले भारत और श्रीलंका देशों में कुल 248 स्थानों की पहचान की गई है। इन स्थानों को विकसित करने और उन्हें सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन सर्किट के हिस्से के रूप में प्रदर्शित करने की भारत सरकार की योजना है। उत्तर प्रदेश में राम वन गमन पथ 4550 करोड़ रुपये के व्यय से विकसित किये जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख स्थान अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और चित्रकूट हैं।

छत्तीसगढ़ में राम वन गमन परिपथ के 75 स्थानों को चिह्नित किया गया है। प्रथम चरण में 9 स्थलों सीतामढ़ी हरचौका (कोरिया), रामगढ़ (सरगुजा), शिवरी नारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा सप्तऋषि आश्रम (धमतरी), जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) का विकास किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार प्राथमिकता के आधार पर राम के जीवन को जीवंत करने में जुटी है। पथ प्रवर्धन का पाथेय चाहे जो हो, अमृत काल में इसे सांस्कृतिक संवर्धन के रूप में देखा जा रहा है। □





# उमस से राहत देने वाले

## आहार



**मा** नसूनी सीजन में बरसात होने तक तो मौसम ठीक रहता है लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो लोगों का सामना उमस से पड़ ही जाता है। उमस या ह्यूमिडिटी से लोगों का हाल इस कदर बेहाल हो जाता है यह बताने की जरूरत नहीं। उमस के चलते लोगों को घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसकी खास वजह यह होती है कि पसीना वाष्पित होने के बजाय शरीर से चिपक जाता है। जिससे चिपचिपाहट महसूस होने से अजीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में एक तरफ जहां घर को हवादार रखना चाहिए तो वहीं खाने में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करना चाहिए जिससे शरीर के अंदर गरमी कम होगी। बल्कि हाईड्रेड लेवल भी बना रहेगा।



उमस में पर्याप्त पानी का सेवन करते रहने की जरूरत है। शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी के साथ-साथ नारियल पानी और छाछ का सेवन भी लाभप्रद है।

वैसे तो खीरे का उपयोग सलाद के रूप में काफी किया जाता है। लेकिन बरसात में इसे

आहार का मुख्य हिस्सा बनाए जाने की जरूरत है। क्योंकि खीरे में पानी की मात्रा अत्यधिक होती है। इसलिए ह्यूमिडिटी से बचने का यह अति उत्तम विकल्प है।



उमस भरे मौसम में दही का सेवन सबसे लाभप्रद उपाय है। दही पेट को स्वस्थ रखने में मददगार होता है और बारिश के दौरान होने वाली पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है।

इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटैशियम की मात्रा भरपूर होती है। इन



तत्वों के चलते शरीर की गर्मी को कम करने में मदद मिलती है। बॉडी टेम्परेचर को सही और संतुलित रखने के लिए नारियल पानी का



सेवन प्रतिदिन करना चाहिए।

संतरे में नमी की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन से शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाती है। साथ ही इलेक्ट्रोलाइट भी संतुलित रहती है। यह विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर को हाईड्रेट भी करता है।

मानसून में शरीर में पानी का लेवल संतुलित रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए लो फैट दूध का सेवन उपयोगी है। यह इलेक्ट्रोलाइट और प्रोटीन लेवल को रिस्टोर करता है।





# दीपिका का शादी पर मंत्र

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने शादी के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा है कि कैसे इंसान से शादी करनी चाहिए।

दीपिका ने सोशल मीडिया पर अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने के बारे में एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में अपने पति रणवीर सिंह को भी टैग किया।

उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फीड में एक नोट शेयर करते हुए कहा - अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करें। मैं यह बात हल्के में नहीं कह रही हूँ। वास्तव में आप जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं उसमें सबसे मजबूत, सबसे खुशहाल दोस्ती पाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे कम्फर्ट एक हेल्थी मैरिटल लाइफ के प्रमुख स्तंभों में से एक है। साथ ही दीपिका ने यह भी साझा किया कि किसी को भी अपने पार्टनर के सामने दिल खोलकर हंसने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वह कितना भी शर्मनाक क्यों न लगे। एक ऐसा पार्टनर ढूँढें जो आपको हसते हुए देखकर खुश हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आप हंस सकते हैं उस तरह की हंसी जिससे आपके पेट में दर्द होने लगता है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार न करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जो आपको उनके साथ मूर्ख बनने देता है। सुनिश्चित करें कि वे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको भी रोने देते हैं। इस तरह का प्यार कभी कम नहीं होता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति से शादी करें जो जुनून, प्यार और पागलपन को एक साथ लाकर आपके साथ आगे बढ़ता हो। एक ऐसा प्यार जो कभी कम न हो। भले ही पानी गहरा और अंधेरा हो। दीपिका और रणवीर ने 2018 में इटली में शादी की थी और दोनों पहली बार फिल्म 'गोलियों की रासलीला राम-लीला' में काम किया था।

## रकुल को नहीं चाहिए स्मार्ट दूल्हा

'अय्यारी', 'शिमला मिर्ची', 'डॉक्टर जी' जैसी फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह इन दिनों शादी को लेकर चर्चा में हैं।

जहां तक रकुल की बात है तो उन्हें अपने लिए हैंडसम नहीं बल्कि बुद्धिमान लड़का चाहिए। अपनी इस बात का और खुलासा करते हुए वे कहती हैं कि मुझे कभी भी कोई लंबी-चौड़ी हाईट वाला या स्मार्ट दिखने वाला लड़का पसंद नहीं आता है। क्योंकि मैं स्मार्टनेस पर नहीं मरती। मुझे हमेशा से समझदार लड़के पसंद आते हैं। जिनके साथ मैं घंटों कुछ अच्छी बातें कर सकूँ।

रकुल का कहना है कि मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, जिसे बस अपने लक्स की ही पड़ी रहती हो। भले ही वह बहुत

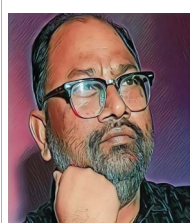
बड़ा आदमी न हो ले कि न उस का समझदार और बुद्धिमान होना जरूरी है।

वैसे रकुल का नाम पिछले कुछ समय से जैकी भगनानी के साथ जोड़ा जा रहा है।





# मजबूत भाजपा को मजबूत चुनौती मिल सकेगी?



**हेमंत तिवारी**  
मो.-9889433333



**अ** गले साल होने वाले लोकसभा के आम चुनाव का चैंपियन कौन होगा, फैसला करने के लिए एक मर्तबा उत्तर प्रदेश फिर से तैयार है। राष्ट्रीय स्तर पर दो बड़ी सेनाएं एनडीए और I.N.D.I.A. ने अपनी व्यूह रचना शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए बने विपक्ष के इस गठबंधन से देश के कई हिस्सों में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को काफी मुश्किलें आ सकती हैं, ऐसे में 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश इस बार उसके लिए कमाऊ पूत की बड़ी भूमिका में आ गया है।

वैसे तो नए मिजाज और अंदाज वाली मोदी-शाह युग की भाजपा के दौर में यूपी ने लगातार सबसे धांसू प्रदर्शन किया है, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ सभी 80 सीटें जीतने का दावा कर दिया है। वर्ष 2014 में भाजपा को अपने सहयोगी दल अपना दल के साथ 73 सीटें मिली तो सपा बसपा के बड़े गठबंधन के बावजूद भाजपा 64 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसी बीच पार्टी ने यूपी में लगातार दो बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है।

इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब विपक्षी दल नींद मुद्रा में रहते हैं तो भाजपा अगले चुनाव के संभावित कमजोर पक्षों के दुरुस्तीकरण अभियान में लगी रहती है और इसी वजह से माना जाता है कि चुनावी तैयारियों में भाजपा और विपक्ष के बीच पसेरी और पासंग का अंतर है। पिछले छह महीने से पार्टी पिछले

चुनाव में हारी हुई 16 सीटों, जिसमें वह दो पर हुए उपचुनाव जीत चुकी है, के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटी हुई है। पूर्वांचल की कई सीटों पर ठीक असर रखने वाले ओमप्रकाश राजभर के साथ ही दारा सिंह चौहान जैसे नेता फिर भाजपा के पाले में आ गए हैं तो पश्चिम में जयंत चौधरी पर भी पार्टी की गहरी नजर है।

राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के खिलाफ बने गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी यूपी है, जहां उसे सिर्फ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर ही निर्भर रहना है। बसपा प्रमुख मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2014 में यूपी में सत्ता रहते समाजवादी पार्टी को लोकसभा की कुल पांच सीटों पर ही सफलता मिली थी, जबकि अगले चुनाव में मायावती के साथ मारक कहे जा रहे गठबंधन के बावजूद उसे फिर पांच ही सीटें मिलीं। हां, 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को करीब पैंतीस फीसद वोट मिले और इसी बुनियाद पर अखिलेश यादव ने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) फार्मूले पर चलने का ऐलान किया है। यहां ध्यान योग्य बात यह है कि 2014 में मोदी के आने के साथ ही यूपी में गैर यादव पिछड़ों का सर्वाधिक समर्थन भाजपा के साथ है और बहुसंख्य दलित बसपा के साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यकों का अधिसंख्य वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया था। ऐसी सूरत में पीडीए का मामला जमीन से ज्यादा हवा में दिखाई दे रहा है। बेशक कांग्रेस यहां बेहद कमजोर है लेकिन इस बार मुस्लिम उसकी ओर भी निगाह किए हैं। बेहतर उम्मीदवार की स्थिति में यह वोट उसके पक्ष में भी जा सकता है।

यूपी के मामले में मायावती का रुख अहम भूमिका अदा करेगा। हाल के सालों में उनके कदम भाजपा के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं और यही सिलसिला जारी रहा तो मोदी का रास्ता आसान रहेगा।

कर्नाटक चुनाव जीतने और राहुल गांधी को लेकर हुई हालिया राजनीति के बाद कांग्रेस में उत्साह है। समझा जाता है कि इस बार राहुल और प्रियंका गांधी यूपी से चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। ऐसी सूरत में पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है।

दरअसल कांग्रेस यूपी में अपनी खोई हुई



सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एकदम से बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद पार्टी यहां अपनी जड़ें मजबूत करने से कामयाब नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ नया कर सकती है। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कोई सियासी दांव चल सकती है। इन कयासों को अब प्रियंका के पति राबर्ट वाड्रा ने भी हवा दे दी है। बता दें कि राबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की है। राबर्ट वाड्रा ने कहा है कि उनकी पत्नी प्रियंका को संसद में होना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक सांसद की सारी योग्यताएं हैं।

प्रियंका गांधी के पति और सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी की काफी तारीफ की है। राबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका को लोकसभा में होना चाहिए। लोकसभा में जाने के लिए उसके पास सारी योग्यताएं हैं।

राबर्ट ने कहा, 'प्रियंका लोकसभा में काफी अच्छा करेंगी। वह संसद में जाने की हकदार हैं। मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी इस बारे में सोचेगी और प्रियंका के लिए भविष्य के लिए योजनाएं बनाएगी।

कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी प्रियंका गांधी के भविष्य को लेकर गंभीर है और इसको लेकर पार्टी के अंदर विचार होना शुरू हो गया है। ऐसे में अब राबर्ट वाड्रा ने भी प्रियंका के चुनाव लड़ने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा किस रूप में दिखाई देती हैं। □

hemant.jansandesh@gmail.com

India's Leading Institute for becoming an IAS



**आकार IAS**

इण्टर (12th) के बाद IAS/PCS की तैयारी करें

**Think About IAS/PCS**

JUST AFTER 12TH

Age group  
15-20 year

**Junior IAS Batch (3 Year Course)**  
**(For 12th Passed Student)**

After **10th** Five Year Integrated Programme for **IAS/PCS**

**GENERAL STUDIES**

PRE CUM MAINS

Hindi & English Medium

**ADMISSION OPEN**

for **IAS/PCS 2024**

**Batch Time- 8:30 AM | 6:00 PM**

 0522-4044438, 9519483938, 9935888651, 9129033494

**Head Office:** B-59, Sec-H, Opp. Axis Bank, Near Puraniya Chauraha, Aliganj, Lucknow

**Our Centre:** 1/803 Vardhan Khand, Gomti Nagar Extension, Near CMS Cambridge Branch, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010

Follow us-    

**Website:** [www.aakarias.co.in](http://www.aakarias.co.in)

To download the **AAKAR IAS App**  
get the QR code scan







नारी सुरक्षा  
नारी सम्मान  
नारी स्वावलंबन



## सशक्त नारी, सशक्त प्रदेश

<b>1090</b> वीमेन पॉवर लाइन	<b>181</b> महिला हेल्पलाइन	<b>1076</b> मुख्यमंत्री हेल्पलाइन	<b>112</b> पुलिस आपातकालीन सेवा	<b>1098</b> चाइल्ड लाइन	<b>102</b> स्वास्थ्य सेवा	<b>108</b> एम्बुलेंस सेवा
-----------------------------------	----------------------------------	---	--	-------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

